04 - पश्चिमी यूपी में उम्मीद से भरी सपा की चुनावी तैयारी

05 - नाना फड़नवीस : मराठा कूटनीति का चाणक्य

06 - डीसैलिनेशन प्लांट: समुद्र के पानी को पेयजल में बदलने का जतन

07 - फार्मर रजिस्ट्री सहित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी...

A Daily News Magazine
इंदौर
शुक्रवार, 13 मार्च, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 159, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

अमेरिका से अपने रिश्तों में हमें मासूमियत पीछे छोड़नी होगी

आर. जगन्नाथन

अमेरिकी उप-विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसे कई लोग भारत के साथ अपनी साझीदारी के बारे में अमेरिका के नजरिए का खास खुलासा करने वाली, मगर असंवेदनशील टिप्पणी कह सकते हैं। 5 मार्च को 'रायसीना डायलॉग' में दिए अपने बयान के शुरू में तो लैंडौ ने भारत की बड़ी तारीफ की कि वह इस सदी में कितनी ऊंचाई को छूने वाला है, कि भारत और अमेरिका की साझीदारी किस तरह दोनों के हित में है जिससे दोनों को ही लाभ होने वाला है। लेकिन इस सब पर उन्होंने यह कहकर पानी डाल दिया कि 'लेकिन, भारत को समझ लेना चाहिए कि हम भारत के मामले में फिर से वैसी गलतियां नहीं करने वाले हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के मामले में की थी और यह कहा था कि हम आपको इन सभी बाज़ारों का विकास करने देंगे, और इसके बाद हमने जाना कि आपलोग हमें कई व्यापारिक मामलों में पीछे छोड़ रहे हैं। हम इस बात की पूरी व्यवस्था करेंगे कि हम जो भी करेंगे वह हमारे लोगों के लिए उचित होगा। क्योंकि अंततः हमें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की सरकार को अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होना है।

अब सवाल यह है कि लैंडौ के इस बयान का क्या आशय क्या यह था कि अमेरिका भारत को ऊंचाई छूने में और कुछ मामलों में उससे होड़ लेने में मदद तो नहीं ही करेगा बल्कि जहां भी संभव होगा वहां उसे वैश्विक रूप से कमजोर करने की ही कोशिश करेगा?

इधर कुछ अरसे से भारत ने खामोशी से यह कबूल लिया है कि अमेरिका उसका मित्र-शत्रु है, यानी कुछ मामलों में उसका मददगार, तो कुछ दूसरे मामलों में एक अड़ंगा। बात जब भारत के उत्कर्ष की आती है तब उसके उभार की रफ्तार को धीमा करने में चीन और अमेरिका, दोनों का एक अबोला स्वार्थ है। इतिहास पर नजर डालना बेहतर होगा। 1971 में हेनरी किसिंजर के चीन दौरे के बाद अमेरिका ने चीन को सोवियत संघ के मुक़ाबले खड़ा करने के लिए तैयार करने का फैसला किया। वहां कुछ अरसे बाद माओ का युग फीका पड़ गया तब चीन ने तंग श्याओ पिंग के नेतृत्व में अपने यहां सुधारों को लागू करने के लिए अपनी ओर अमेरिका के झुकाव का फायदा उठाया। चीन ने आंतरिक सुधार करके, खुद को सरकार आधारित मरणासन्न अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील किया। इसने कई पश्चिमी कंपनियों को अपना सप्लाई चेन चीन में स्थानांतरित करने, अपनी उत्पादन लागत कम करने की सुविधा उपलब्ध कराई, बेशक इससे चीन को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने की ताकत भी मिली। उस दौर में, अमेरिका ने चुपके से चीन के साथ अनुकूल सौदा करके उसे विश्व व्यापार संगठन में दाखिल करवा दिया और उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ताइवान वाली दिलवा दी। चीन ने इस सबका फायदा उठाते हुए अपने यहां आंतरिक सुधारों को तेजी से लागू किया और हाल तक एशिया के शेर बने देशों के मुक़ाबले ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि की।

बेशक यह कहना सही होगा कि अमेरिका ने चीन के उत्कर्ष में परोक्ष सहायता की, लेकिन यह कहना भी उतना ही सही होगा कि अमेरिका ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के उत्कर्ष में; और दक्षिण कोरिया, होंगकोंग (चीन में इसकी वापसी से पहले), थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस आदि-आदि के उत्कर्ष में भी मदद की। लेकिन अमेरिका ने यह सब सिर्फ अपनी उदारता के कारण नहीं किया। यह नीति उसके भू-राजनीतिक लक्ष्यों के लिए माकूल थी, और इसने अमेरिकी उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद यथासंभव न्यूनतम कीमत में उपलब्ध कराए। इस नीति ने डॉलर को वैश्विक मानक मुद्रा बनाने के विशेषाधिकार भी अमेरिका को दिए जिसके बूते उसे अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए निरंतर उधार लेने की सुविधा हासिल हो गई। यह तब भी जारी रहा जब अमेरिका ने रिचर्ड निक्सन के राज में डॉलर का रिश्ता सोने से तोड़ दिया। इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि उसने वित्तीय नतीजों और मुद्रास्फीति की परवाह किए बिना डॉलर छापने का अधिकार हासिल कर लिया।

यही बात आप दुनिया को पछाड़ने वाली भारतीय सॉफ्टवेयर सेवाओं और दवा उद्योग के लिए अमेरिकी 'समर्थन' के बारे में भी कह सकते हैं। इससे भारत को जबकि उच्च स्तरीय नौकरियों के रूप में भारी लाभ हुआ है, अमेरिकी कंपनियां अपनी तकनीकी क्षमताओं में सुधार करके ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी बन पाई हैं। भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों की स्थापना ने भी अमेरिकी कंपनियों को न केवल अपनी तकनीकी ताकत बढ़ाने में मदद की है बल्कि अपनी आपसी प्रक्रियाओं से उभरे ज्ञान को कायम रखने में भी मदद की है। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा के ऊंचे बिल में भारतीय जेनरिक दवाओं के उपयोग से कमी आ रही है।

इसलिए, लैंडौ जब यह कहते हैं कि अमेरिका इन बाज़ारों के विकास में भारत की मदद नहीं करेगा ताकि वह उसे उसके ही खेल में मात न दे, तो वे वास्तव में बेतुकी बात कह रहे हैं। वास्तव में, इसका दूसरा पहलू भी है. भारत यह देख सकता है कि श्रम-मोलभाव आधारित सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात के मामले में अमेरिकी बाज़ारों पर अति निर्भरता के कारण हमने अपने प्रोडक्ट पर और प्लेटफॉर्म विकास की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल, अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजी के मामले में आंशिक गुलाम जैसा बना दिया। लैंडौ के बयान का असली मतलब उनकी मंशा में निहित है। जब उन्होंने यह कहा कि भारत अमेरिका से वैसी मदद नहीं पाने वाला जैसी अमेरिका ने कथित तौर पर चीन को उसके उभार के लिए दी थी, तब उनका मतलब शायद यह था कि अमेरिका तो दरअसल हमारे उत्कर्ष को किसी तरह भंग करने की ही कोशिश करेगा। हमारे पड़ोस में जिस तरह अस्थिरता पैदा हो रही है, और ट्रंप सरकार कथित तौर पर रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर जो टैरिफ थोप रहा है, वह सब इसी तरह की कोशिशों में शामिल मानी जा सकती है।

भारत को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अमेरिका हमारे उत्कर्ष में यथासंभव कई तरह के अड़ंगे लगा सकता है, जिनमें आंतरिक असंतोष और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है जबकि वह हमारी मदद का दिखावा करने के लिए ऐसे क्षेत्रों को चुन सकता है जिनमें हमारी मदद करने से उसे ही लाभ हो।

भारत के लिए चेतावनीः अमेरिकी मंशाओं की मासूमियत पर भरोसा करना भूल जाइए।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

ईरान में तनाव के बीच

होर्मुज पार कर मुंबई पहुंचा तेल टैंकर

● भारतीय कैप्टन के हाथों में थी कमान ● भारत और ईरान की 3 दिनों की चर्चा के बाद मिली सफलता

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आया लाइबेरियाई ध्वज वाला टैंकर ईरान की अनुमति से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर सुरक्षित रूप से मुंबई पोर्ट पहुंच गया। भारत सरकार क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखे हुए है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक लाइबेरियाई ध्वज वाला कच्चे तेल का टैंकर, जिसकी कमान एक भारतीय कप्तान के हाथ में थी, रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर सुरक्षित रूप से मुंबई बंदरगाह पहुंच गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार यह टैंकर सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर आया था।

ईरान की अनुमति के बाद जलडमरूमध्य से गुजरा टैंकर-अधिकारियों के अनुसार टैंकर ने सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया।

ऐसे भारत पहुंचा यह टैंकर ?

मैरिटाइम ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, इस टैंकर ने 1 मार्च को सऊदी अरब के रास तनुरा पोर्ट से कच्चा तेल लोड किया था और 3 मार्च को वहां से रवाना हुआ। 8 मार्च को जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य में ट्रैक किया गया, जिसके बाद यह कुछ समय के लिए ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज ने जोखिम भरे समुद्री क्षेत्र से गुजरते समय अपना ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एआईएस) ट्रांसपोंडर बंद कर दिया था। यह प्रणाली जहाज की पहचान, स्थिति, गति और दिशा की जानकारी प्रसारित करती है, जिससे समुद्री यातायात को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

ईरान के नए सुप्रीमो मोजतबा की चेतावनी, मिडिल ईस्ट में 'यूएस बेस बंद करो, या हमले झेलने को तैयार रहो' होर्मुज के रास्ते बंद ही रहेंगे

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। हमारे मारे गए बच्चों का बदला जरूर लेंगे। जंग कब रोकना है यह तेहरान करेगा। अमेरिका को कड़ी चेतावनी देकर कहा होर्मुज जलडमरुमध्य बंद ही रहेगा और एक लीटर तेल भी यहां से नही जाएगा।

जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से तीन बार की बात, जहाजों की सुरक्षा पर हुई चर्चा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच हाल के दिनों में तीन बार बातचीत हुई है। पिछली बातचीत में शिपिंग की सेफ्टी और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर बात हुई थी। इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जायसवाल ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री अपने ईरानी काउंटरपार्ट से बात कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में तीन बार बातचीत हुई है। जहां तक युद्ध के असर की बात है, तो यह सबके सामने है कि आस-पास क्या हो रहा है। हम में से कई लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ा है, सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों और देशों पर इसका असर पड़ा है।

● **पीएम मोदी ने गल्फ लीडर्स से की बात**- रणधीर जायसवाल ने बताया कि लड़ाई शुरू होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने गल्फ में कई लीडर्स से बात की है। इन बातचीत में, उन्होंने बातचीत और डिप्लोमेसी की जरूरत पर जोर दिया ताकि जल्दी शांति लौट सके। उन्होंने सिविलियन कैजुअल्टी से बचने की जरूरत पर भी जोर दिया और सिविलियन्स की सुरक्षा पर फोकस किया। त्रष्ट देशों में हमारी एक बड़ी इंडियन कम्युनिटी है और उनकी सिक्योरिटी और वेलफेयर सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस बात पर जोर दिया गया। हमने कई मामलों में, देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के उल्लंघन की भी निंदा की।

सीएम यादव ने शिवराज के साथ की कृषि भवन में बैठक

अब सरसों पर भावांतर का लाभ, तुअर की पूरी फसल खरीदेगी सरकार

नईदिल्ली/भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। खास बात यह रही कि इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान से सीएम ने मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ मुलाकात की है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन वे एक निजी शादी समारोह में शामिल होने गए थे।

शिवराज-मोहन और प्रहलाद के बीच चर्चा- तीनों दिग्गजों के बीच हुई बैठक के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि खेती से जुड़े इन मुद्दों पर चर्चा हुई है।

सरसों उत्पादकों को भावांतर का तोहफा - लंबे समय से लंबित सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दे दी है। इससे प्रदेश के लाखों सरसों उत्पादक किसानों को बाजार और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधे खाते में मिलेगी।

तुअर की 100 प्रतिशत सरकारी खरीद- शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को स्वयं स्वीकृति पत्र सौंपा, जिसके तहत अब प्रदेश के किसानों की पूरी की पूरी तुअर फसल सरकार खरीदेगी। यह दलहन उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

2026 किसान कल्याण वर्ष का रोडमैप- वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसे तिलहनों पर भी विशेष फोकस रहेगा।

सीएम करेंगे 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपये की राशि अंतरित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के शबरी माता मंदिर घाटीगाँव में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों के बैंक खातों में 1836 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण करेंगे। यह राशि योजना की 34वीं किश्त के रूप में बहनों को प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में योजना के अंतर्गत नवंबर माह से मासिक सहायता में 250 रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे अब पात्र हितग्राही बहनों को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। प्रदेश में जून 2023 से प्रारंभ हुई यह योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान का नया आधार बनी है। जून 2023 से फरवरी 2026 तक योजना के तहत 33 किश्तों का नियमित अंतरण किया जा चुका है। इस अवधि में 54,140 करोड़ रुपये की राशि बहनों के खातों में सीधे अंतरित की गई है।

इन कार्यों का करेंगे भूमि-पूजन व लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव लाड़ली बहना सम्मेलन में ग्वालियर जिले के अंतर्गत लगभग 122 करोड़ लागत के 54 कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। इनमें लगभग 62 करोड़ के 19 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 60 करोड़ रुपये लागत के 35 कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा जिन कार्यों का लोकार्पण किया जायेगा उनमें लगभग 40 करोड़ की लागत से सांदिपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुलैथ का भवन और 9.11 करोड़ की लागत से डाडा खिरक तिघरा मार्ग पर सांक नदी पर नव निर्मित उच्च स्तरीय पुल शामिल हैं। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र बन्हेरी तथा ग्वालियर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में नव निर्मित सड़कें शामिल हैं।

शरद की सुबह

तू न तान की मरोर
देख, एक साथ चल,
तू न ज्ञान-गर्व-मत्त..
शोर, देख साथ चल।

सूझ की हिलोर की
हिलोरबाज़ियाँ न खोज,
तू न ध्येय की धरा..
गुंजा, न तू जगा मनोज।

तू न कर घमंड, अग्नि,
जल, पवन, अनंग संग
भूमि आसमान का चढ़े
न अर्थ-हीन रंग।

बात वह नहीं मनुष्य
देवता बना फिरे,
था कि राग-रंगियों..
घिरा, बना-ठना फिरे।

बात वह नहीं कि..
बात का निचोड़ वेद हो,
बात वह नहीं कि..
बात में हज़ार भेद हो।

स्वर्ग की तलाश में
न भूमि-लोक भूल देख,
खींच रक्त-बिंदुओं..
भरी, हज़ार स्वर्ण-रेख।

बुद्धि यन्त्र है, चला;
न बुद्धि का गुलाम हो।
सूझ अश्व है, चढ़े..
चलो, कभी न शाम हो।

शीश की लहर उठे..
फसल कि, एक शीश दे।
पीढ़ियाँ बरस उठें
हज़ार शीश शीश ले।

भारतीय नीलिमा
जगे कि टूट-टूट बंद
स्वप्न सत्य हों, बहार..
गा उठे अमंद छन्द।

\- पं. माखनलाल चतुर्वेदी

देशभर में एलपीजी की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी कतारें

● इंडक्शन की मांग बढ़ी, अमेजन में प्रोडक्ट की 30 गुना तक बिक्री, कई ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर आउट ऑफ स्टॉक

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान-इजराइल में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट बंद हो गया है। ऐसे में कच्चे तेल की सप्लाई बंद होने के बाद भारत करीब 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदेगा। वहीं जंग की वजह से देशभर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी हैं।

देश में एलपीजी की उपलब्धता की बढ़ती चिंता के बीच की ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन की मांग अचानक बढ़ गई है। कई ई-कॉमर्स साइट्स पर ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन के स्टॉक में खासी कमी देखने को मिल रही है। ब्लिंकिट पर तो लगभग सभी मॉडल आउट ऑफ स्टॉक दिख रहे हैं, जबकि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी कुछ ही ब्रांड मिल रहे हैं।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई पर असर के कारण कई शहरों में लोग एलपीजी सिलेंडर न मिलने से परेशान हैं। इसी वजह से बैकअप के तौर पर इंडक्शन कुकटॉप खरीद रहे हैं। भारत में आमतौर पर इंडक्शन की कीमत 1300 से 2000 से शुरू होती हैं। वहीं, मिड रेंज जाने पर यह 2,000-3,500 में मिलता हैं। प्रीमियम मॉडल 3,500-4,500+ का होता है।

● **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड बिक्री**- ई-कॉमर्स कंपनियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन की बिक्री में तेज उछाल आया है। अमेजन पर बिक्री करीब 30 गुना और फ्लिपकार्ट पर बिक्री करीब चार गुना हो गई।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20°c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 13 मार्च 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

पूरी तरह बदलने वाला है आरएसएस

● प्रांत प्रचारक पद खत्म होगा, यूपी चुनाव में पहला टेस्ट, ऐसा हो सकता है नया स्ट्रक्चर

नई दिल्ली (एजेंसी)। 40 लाख सदस्य और 83 हजार से ज्यादा शाखाओं वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करने वाला है। इसके मुताबिक अब अलग-अलग प्रांत प्रचारकों की जगह एक राज्य प्रचारक होगा। क्षेत्र प्रचारकों की संख्या भी कम होगी। जिला, तहसील, ब्लॉक और गांवों तक कार्यकर्ताओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। बदलाव का प्रस्ताव हरियाणा में पानीपत के समालखा गांव में 13, 14 और 15 मार्च को होने वाली बैठक में पेश होगा।

इसकी जरूरत क्यों पड़ी? –इसका जवाब बैठक के आयोजकों में से एक आरएसएस के पदाधिकारी देते हैं। वे कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन को पहले से ज्यादा टारगेट और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए ये बदलाव जरूरी हैं। ये एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है। संघ की ताकत बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचाने और देश के हर व्यक्ति तक संघ की

पहुंच बनाने की प्रक्रिया है। सोर्स के मुताबिक, बैठक में सभी सुझावों के साथ एक प्रस्ताव बनेगा, जिसे सितंबर 2026 की बैठक में पारित किया जाएगा। फिर जनवरी-फरवरी 2027 तक सभी जगह लागू किया जाएगा।

100 साल में दूसरी बार इतना बड़ा बदलाव

क्या इतना बड़ा बदलाव पहली बार हो रहा है? : सोर्स ने जवाब दिया, बदलाव तो संघ में होते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा बदलाव दूसरी बार है। पहली बार 1949 में हुआ था, जब संघ ने लिखित संविधान बनाकर सरकार को सौंपा था। उसी वक्त संघ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी स्वीकार किया था। उस वक्त ढांचे और काम करने के तरीकों में भी कई बड़े बदलाव किए गए थे। उसके बाद बड़ा बदलाव ड्रेस में किया गया, लेकिन ढांचे में कुछ खास नहीं बदला गया था। पिछले 4 साल से इसी बदलाव के लिए चर्चा चल रही थी, जो अब ठोस रूप में आ गई है।

संघ की रीढ़ प्रांत प्रचारक व्यवस्था खत्म होगी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर अब तक राज्य कोई इकाई नहीं थी। बड़े राज्य कई प्रांतों में बंटे हैं। इनके प्रांत प्रचारक जमीनी और शीर्ष कार्यकर्ताओं के बीच कड़ी का काम करते थे। अब नए स्ट्रक्चर में प्रांत प्रचारकों की जगह राज्य प्रचारक होंगे। अभी देशभर में करीब 45 प्रांत प्रचारक हैं। नए बदलाव को उत्तर प्रदेश के जरिए समझिए। यहां अभी 6 प्रांत हैं।

- ब्रज– मथुरा, आगरा, अलीगढ़
- अवध– लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी
- मेरठ– पश्चिमी यूपी का हिस्सा (मेरठ, सहारनपुर)
- कानपुर– कानपुर, फतेहपुर
- काशी– वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर
- गोरक्ष–गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर

हर प्रांत में प्रचारक होता है। अब उनकी जगह एक राज्य प्रचारक होगा। यानी 6 प्रांत प्रचारक की बजाय सिर्फ एक राज्य प्रचारक होगा। इसके ऊपर क्षेत्र प्रचारक बने रहेंगे।

संक्षिप्त समाचार

मप्र के सागर में दिल दहलाने वाली घटना

● आधी रात कुएं में चार बेटियों को फेंककर मां ने लगाई फांसी

भोपाल/सागर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। केसली थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में एक महिला का शव बेर के पेड़ पर फंदे से लटका मिला, जबकि खेत में बने कुएं से उसकी चार मासूम बेटियों के शव बरामद हुए। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय सविता लोधी का शव गुरुवार सुबह गांव के पास एक बेर के पेड़ पर लटका मिला। ग्रामीणों ने जब आसपास के कुएं में देखा तो उसमें सविता की चार बेटियों (7 साल, 5 साल, 3 साल और चार महीने की मासूम) के शव तैरते हुए दिखाई दिए। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

● अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा

लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी, नेता प्रतिपक्ष को कभी नहीं रोका, नियम सबसे ऊपर

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर दो दिनों तक चली चर्चा के बाद स्पीकर ओम बिरला पहली बार आसन पर पहुंचे और सदन को संबोधित किया।

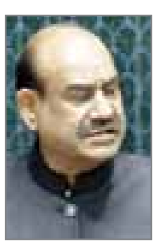

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है और किसी भी नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी, संसद के नियमों से ऊपर नहीं हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आज पहली बार आसन पर आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है और नेता प्रतिपक्ष को कभी नहीं रोका गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद के नियम सर्वोपरि हैं और कोई भी व्यक्ति नियम से ऊपर नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हों।

भगवान रंगनाथ ने होली खेली, ढोल-नगाड़ों पर विदेशी भी झूमे

● मथुरा में कांच के विमान में विराजमान होकर निकले

मथुरा (एजेंसी)। गुरुवार को कांच के विमान (रथ) में माता गोदा के साथ विराजमान होकर भगवान रंगनाथ की सवारी निकली। ढोल–नगाड़ों पर भक्त झूमते नजर आए। विदेशी सैलानियों ने भी

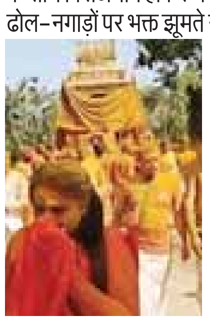

जमकर डांस किया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने भगवान का प्रसादी रंग–गुलाल भक्तों पर बरसाया। होली और भक्ति में सराबोर भक्तों ने अपने आराध्य के साथ जमकर होली खेली। जहां से भी भगवान की सवारी गुजरी, वहां माहौल अबीर–गुलाल से रंग गया। सवारी के दौरान भक्तों ने पारंपरिक अंदाज में लट्ठ बरसाकर होली खेली। दुल्हन जैसी सजी महिलाओं ने हुरियारों पर लाठियां बरसाईं। इस दौरान भगवान के जयकारे गूंज उठे। महिलाएं, पुरुष, बड़े–बुजुर्ग रंग–गुलाल में रंगे नजर आए।

आरएन रवि ने ली पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद की शपथ

ममता समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को कोलकाता स्थित लोकभवन में 22वें राज्यपाल के रुप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें सॉजय पॉल ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे।

भोपाल में पत्नी से विवाद के बाद युवक का सुसाइड

बड़सास से कॉल पर हुई थी बहस, पत्नी ने कहा–सरेराह कटवा कर फिकवा दूंगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के ईंटखेड़ी इलाके में रहने वाले क्रेन ऑपरेटर ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पत्नी से विवाद के चलते उसने यह कदम उठाया है। सुसाइड से पहले युवक ने अपने भाई और पत्नी को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने लिखा कि मैं अपनी घरवाली कृष्णा की वजह से अपनी जान दे रहा हूं। इसकी जिम्मेदार वही है।

मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। युवक के शव को गुरुवार सुबह करीब 5:45 बजे परिजनों ने घर में स्थित कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा था।

27 वर्षीय केशव धानक पुत्र घिसीलाल धानक जगदीशपुर थाना ईंटखेड़ी क्षेत्र का रहने वाला था। वह क्रेन ऑपरेटर था और 4 साल पहले कृष्णा नाम की युवती से शादी हुई थी। मृतक के चाचा विनोद का आरोप है कि शादी के बाद भी बहू का दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग था। उसे दूसरे युवक से बात करते भतीजे ने रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद से ही दोनों के बीच विवाद बना

केशव धानक, मृतक

रहता था।

बहू आए दिन मायके चली जाती थी, कई-कई दिन तक लौटती नहीं थी। उसकी मां और बड़ी बहन भी भतीजे को कॉल कर प्रताड़ित करती थी। लगातार भतीजे को कॉल कर गंदी-गंदी गालियां दी जाती थीं और फर्जी मुकदमा लगवा कर जेल भिजवाने की धमकी देती थी। आए दिन की प्रताड़ना और बदसलूकी से परेशान जाकर भतीजे ने सुसाइड किया है।

विनोद ने बताया कि खुदकुशी से पहले बहू की बड़ी बहन ने भतीजे को कॉल कर गालियां दी थीं। जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है और हमने यह रिकॉर्डिंग पुलिस को भी सौंप दी है। हम भतीजे के लिए न्याय चाहते हैं।

कॉल पर बोली पत्नी और उसकी बड़ी बहन कटवा कर फिकवा देंगे

चाचा विनोद की ओर से पुलिस को चार ऑडियो क्लिप दी गई हैं। इन सभी में बहू उसकी मां और उसकी बड़ी बहन केशव को गालियां देती हैं। सरे राह कटवा कर फेंकने की धमकी देती हैं। फर्जी महिला अपराध में जेल भिजवाने की धमकी देती सुनाई दे रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी ऑडियो को जांच में शामिल किया गया है।

आरएन रवि ने ली पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद की शपथ, सीएम ममता समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को कोलकाता स्थित लोकभवन में 22वें राज्यपाल के रुप मं पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें सॉजय पॉल ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे।

● एलपीजी को लेकर संसद के अंदर तकरार, बाहर नारेबाजी

नरेंदर भी गायब सिलेंडर भी गायब

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर हंगामा किया। सांसदों ने संसद के बाहर 'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब' के नारे लगाए।

राहुल गांधी ने सरकार से एलपीजी की कमी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया, इसलिए बड़ी समस्या आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के नोटिस के बाद संसद गैस संकट पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। इससे पहले लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला 10 फरवरी के बाद अध्यक्ष की चेयर पर बैठे।

विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को खारिज हो गया।

संसद की सीढ़ियों पर बैठ कर विपक्ष ने चाय बिस्कुट खाए– राहुल गांधी समेत विपक्ष के सांसदों ने देश में एलपीजी संकट पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। 50 से ज्यादा सांसद मौजूद थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर की सीढ़ियों पर विपक्षी सांसदों के साथ बैठकर चाय और बिस्किट खाए।

भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका

● 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू, अनुचित व्यापार के सबूत मिले तो भारी टैक्स लगेगा

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने भारत और चीन समेत अपने 16 प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ 'सेक्शन 301' के तहत नई जांच शुरू कर दी है। 'सेक्शन 301' अमेरिका को उन देशों पर एकतरफा टैक्स बढ़ाने की शक्ति देता है, जो उसकी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहे हो। पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ को अवैध बताने के बाद, प्रशासन अब नए कानूनी रास्तों से टैरिफ का दबाव वापस बनाने की तैयारी में है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के मुताबिक, इस जांच के कारण इस साल गर्मियों तक भारत, चीन, यूरोपीय संघ और मैक्सिको जैसे देशों पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं।

अमेरिका ने किन देशों के खिलाफ जांच शुरू की है?

ट्रम्प प्रशासन ने कुल 16 ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू की है। इनमें भारत, चीन, यूरोपीय संघ (ईयू), जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं।

● संसद में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी

देश में अभी पर्याप्त पेट्रोल-डीजल और गैस लंबे समय तक हालात से निपटने को तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में एलपीजी संकट पर लोकसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 40 देशों से क्रूड ऑयल ले रहा है। गैस-सिलेंडर पर पैनिक होने की कोई बात नहीं है।

हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में वेस्ट एशिया संकट पर कहा कि एनर्जी के इतिहास में दुनिया ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। होर्मुज स्ट्रेट को इतिहास में पहली बार कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद कर

दिया गया। संघर्ष पैदा करने में कोई भूमिका नहीं है, भारत को इसके नतीजों से निपटना होगा। भारत की क्रूड ऑयल सप्लाई की स्थिति सुरक्षित है।

● संकट से निपटने सरकार के जरूरी 5 कदम

- **हाई–लेवल कमेटी बनाई–** संकट को देखते हुए एक हाई–लेवल कमेटी बनाई है, जो सप्लाई की समीक्षा करेगी।
- **एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू–** गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में 'एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955' लागू कर दिया है।
- **25 दिन बाद होगी एलपीजी बुकिंग :** घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक होगा।
- ओटीपी और बायोमेट्रिक अनिवार्य
- एलजीपी उत्पादन बढ़ाने का आदेश

ऊर्जा संकट पर बहस

लोकसभा में गुरुवार को ईरान–इस्राइल युद्ध के चलते पैदा हुए उर्जा संकट पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ईरान युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। देश में एलपीजी को लेकर संकट है। स्ट्रीट वेंडर्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है।

वहीं एपस्टीन का नाम लेते ही संसद में हंगामा हो गया। अमेरिका कौन होता है हमें यह बताने वाला कि हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे गैस खरीदेंगे? छोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं।

● *इजरायल का बड़ा धमाका, ईरान में न्यूक्लियर कंपाउंड को बनाया निशाना; तेहरान का आसमान हुआ काला*

हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागीं

तेलअवीव/नईदिल्ली (एजेंसी)। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष तेजी से गंभीर संकट में बदल गया है। यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान में कई जगहों पर हवाई हमले किए।

इसी बीच गुरुवार को इजराइल ने ईरान के तालेकान न्यूक्लियर कंपाउंड पर हमला किया। इस दौरान तेहरान में जोरदार धमाके हुए। मीडिया के अनुसार शहर के पश्चिमी हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजरायल ने फारस की खाड़ी में स्थित ईरानी द्वीपों पर हमला किया तो तेहरान कोई संयम नहीं रखेगा।

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। इजराइल को ईरान के साथ-साथ पड़ोसी देश लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाए जा सकेंगे ज्ञानेश कुमार?

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए 200 से अधिक सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे कल संसद के किसी एक सदन को सौंपा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी नेताओं ने कुमार पर सात आरोप लगाए गए हैं।

लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई है। एक सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

हस्ताक्षर करने में सांसदों ने दिखाया उत्साह– सूत्र के मुताबिक, इस नोटिस को कल किसी एक सदन में जमा किया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि किस सदन में सौंपा जाएगा। इस बीच, विपक्ष के एक नेता ने कहा कि सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने में काफी उत्साह दिखाया है। आवश्यक संख्य पहले ही पूरी हो जाने के बावजूद गुरुवार को कई सांसद इस नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आए।

● 200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर किए हस्ताक्षर, क्या है नियम

क्या कहता है नियम?

नियम के मुताबिक, सीईसी को पद से हटाने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। वहीं, राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।

आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी किए हस्ताक्षर– सूत्र ने बताया कि नोटिस पर इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक अन्य सूत्र ने कहा, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि आप अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है।

सीईसी के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए?

यह पहली बार है, जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। एक उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सात आरोप लगाए गए हैं। इनमें पद पर रहते हुए पक्षपाती और भेदभावपूर्ण आचरण से लेकर चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालने और बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने जैसे आरोप शामिल हैं। विपक्ष दल कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगा चुके हैं कि वह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद करते हैं, खासकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में।

आईएएस अधिकारी के फार्महाउस पर जुए का अड्डा मिला, 18 लोगों से लाखों जब्त

इंदौर। महू क्षेत्र के मानपुर थाना इलाके में पुलिस ने बुधवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फार्महाउस पर चल रहे जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 18 लोगों को गिरफ्तार किया। जबकि, कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। छापे के दौरान भारी मात्रा में नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ग्राम आवलीपुरा में स्थित जिस फार्म हाउस पर यह कार्रवाई हुई, वह महिला आईएएस अधिकारी वंदना वैध और उनके पति अम्बरीश वैद्य के नाम पर दर्ज बताया जा रहा है। वंदना वैद्य वर्तमान में इंदौर में वित्त विकास निगम की प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि मानपुर इलाके के इस फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर जुआ संचालित किया जा रहा है। जानकारी की पुष्टि होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की एक टीम ने देर रात यहां छापा मारा। जब पुलिस दल फार्म

फार्महाउस जिस आईएएस अधिकारी का उन्होंने पुलिस को पत्र लिखा

हाउस पहुंचा तो मुख्य प्रवेश द्वार बाहर से बंद मिला, लेकिन परिसर के भीतर लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने पीछे के रास्ते से अंदर प्रवेश किया। वहां बरामदे में कई लोग ताश के पत्तों के साथ दांव लगाते हुए पाए गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि करीब पांच से छह लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।

13 लाख से ज्यादा नकद मिला - छापे के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 लाख 67 हजार 971 रुपये नकद जब्त किए हैं। इसके अलावा 52 ताश के पत्ते, 10 नई ताश की गड्डियां, 30 मोबाइल फोन और दो कारें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए सभी सामान की कुल कीमत लगभग 28 लाख 67 हजार 971 रुपये आंकी गई है। मामले में जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि इस जुए के नेटवर्क का संचालन जगदीश राठौर उर्फ कुबड़ा नामक व्यक्ति करता है। पुलिस का कहना है कि वह क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर जुए के फड़ चलाने के लिए कुख्यात है और फिलहाल फरार है।

आईएएस ने पुलिस को लिखा - घटना सामने आने के बाद आईएएस अधिकारी वंदना वैद्य ने इंदौर पुलिस आयुक्त, ग्रामीण डीआईजी, ग्रामीण आईजी और मानपुर थाना प्रभारी को एक पत्र भेजकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों के जरिए मिली। उन्होंने बताया कि मानपुर स्थित कृषि भूमि और वहां बना फार्महाउस उनकी निजी संपत्ति है, जिसे सरकारी अभिलेखों में भी घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी लिखा कि इस स्थान का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों और कुलदेवी के पूजन के लिए किया जाता है। परिवार के सदस्य कभी-कभी ही वहां जाते हैं और अधिकतर समय यह स्थान बंद रहता है।

घरेलू गैस, पेट्रोल व डीजल की कमी नहीं, कलेक्टर ने कहा, घबराएं नहीं

होटलों को सिलेंडर की जगह वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह

इंदौर। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इंदौर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। आम उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, अवन्तिका के सेल्स अधिकारी, गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि, एचपीसीएल गैस प्लांट मांगलिया के मैनेजर तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए, आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे। किसी भी उपभोक्ता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

सिलेंडर बुकिंग दस गुना बढ़ी

जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि हाल ही में लोगों में आशंका के कारण बुकिंग में अचानक वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों के आंकड़ों में सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक बुकिंग दर्ज की गई। इससे यह स्पष्ट है कि लोगों में अनावश्यक भय का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि 14 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बुकिंग के आधार पर सिलेंडर मिलते रहेंगे। ऑयल कंपनियों द्वारा केवल इतना बदलाव किया गया कि सिलेंडर की अगली बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को सामान्यतः बुकिंग के तीन दिन के भीतर डिलेवरी घर पर ही ओटीपी के माध्यम से दी जा रही है।

होटलों को वैकल्पिक साधनों की सलाह

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित है। इसलिए होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को अस्थायी रूप से डीजल भट्टी, इंडक्शन, इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक कॉइल जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कलेक्टर ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए और किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होने दी जाए। यदि होटल या अन्य व्यवसायों को घरेलू सिलेंडर दिए जाने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीमित आपूर्ति होगी

बैठक में बताया गया कि शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों के लिए ऑयल कंपनी द्वारा दी गई छूट अनुसार कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी। प्रशासन द्वारा निगरानी के लिए तीन जांच दल गठित किए गए हैं, जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गैस वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पारदर्शिता के उपाय किए

उन्होंने बताया कि गैस वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब सिलेंडर डिलीवरी के समय उपभोक्ता से ओटीपी अनिवार्य रूप से लिया जाएगा, जिससे अनियमितता की संभावना कम होगी। साथ ही, शहर में जहां पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां होटल और रेस्टोरेंट को प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अवंतिका गैस कंपनी ने इस संबंध में त्वरित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है।

समस्या होने पर शिकायत करें

इंदौर में घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की कमी या समस्या नहीं है। प्रशासन के अनुसार शहर में गैस की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि किसी उपभोक्ता को भारत गैस, इंडेन गैस या एचपी गैस के डीलर द्वारा सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो इसकी शिकायत संबंधित कंपनी के कस्टमर केयर नंबरों पर की जा सकती है।

20 दिन में 3750 वाहनों पर कार्रवाई नो पार्किंग पर यातायात पुलिस सख्त

इंदौर। यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाने पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसके तहत 20 दिन में नो-पार्किंग में खड़े 3750 वाहनों पर व्हील लॉक लगाकर कार्रवाई की गई है। यह अभियान पुलिस उपायुक्त (प्रभारी ट्रैफिक) राजेश त्रिपाठी के निर्देशन चल रहा है। इसमें चारों यातायात जोन में पेट्रोलिंग टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। यातायात पुलिस की टीमों ने अपने-अपने जोन में भ्रमण कर निरीक्षण किया और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। जोन-1 के कालानी नगर, एयरपोर्ट रोड, बड़ा गणपति से गौराकुंड, इमली बाजार, अंतिम चौराहा और मरीमाता से बाणगंगा तक, जोन-2 में मालवा मिल से पाटनीपुरा, भमोरी, एलआईजी, रसोमा, मेदांता रोड और विजयनगर क्षेत्र, जोन-3 में जेलरोड, एमटीएच, आरएनटी मार्ग, एमजी रोड, व्हाइट चर्च से दवा बाजार, मधुमिलन, जंजीरवाला, पलासिया से व्हाइट चर्च और घंटाघर से गीताभवन तक तथा जोन-4 में सपना संगीता, टॉवर चौराहा से खातीवाला टैंक, सिंधी कॉलोनी, राजवाड़ा, जवाहर मार्ग, खजूरी बाजार, सराफा और भंवरकुआ से भोलाराम उस्ताद मार्ग तक अभियान चलाया गया।

आधुनिक संसाधनों का उपयोग- पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने पीए सिस्टम, बॉडी वॉर्न कैमरा, क्रेन, सपोर्ट वाहन, व्हील लॉक और पीओएस मशीन का उपयोग कर अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। कई स्थानों पर अनाउंसमेंट के जरिए हजारों वाहनों को हटवाया भी गया। बता दें, यातायात पुलिस पहले वाहन चालकों को समझाइश और चेतावनी देती है, लेकिन नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर व्हील लॉक और क्रेन के माध्यम से चालान की कार्रवाई की जाती है। लगातार हो रही इस कार्रवाई के कारण कई क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम हुई है, जिसकी जिम्मेदार नागरिकों द्वारा सराहना भी की जा रही है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोकथाम के लिए मुहिम

35 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई में 105 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए

इंदौर। जिले में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम के लिए विशेष मुहिम प्रारंभ की गई है। इस मुहिम के तहत घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त

कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने इस कार्रवाई के लिए तीन विशेष दलों का गठन किया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि इन दलों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। दल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगातार विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर स्थिति पर निगरानी रखेंगे। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जहां भी घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया जाएगा, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बुधवार सुबह से चलाए अभियान के तहत तीनों दलों ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। अब तक करीब 35 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 105 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के विरुद्ध आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

भोजशाला के एएसआई सर्वे में कई बड़े खुलासे, 244 शिलालेखों पर छेनी चली

खिलजीकालीन अभिलेख ने दी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की गवाही

इंदौर। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर देश के सबसे संवेदनशील पुरातात्विक और कानूनी विमर्श के केंद्र में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की मैसूर स्थित एपिग्राफी शाखा द्वारा वर्ष 2024 में किए गए वैज्ञानिक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के लगभग 244 शिलालेखों के अक्षरों को जानबूझकर छेनी से मिटाया गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश की गई 2189 पृष्ठों की इस रिपोर्ट पर आगामी 16 मार्च को हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है।

फारसी भाषा में दर्ज सत्य- एएसआई की रिपोर्ट के सबसे विवादित और निर्णायक हिस्से में मालवा सल्तनत के सुल्तान महमूद खिलजी के शासनकाल (1436-1469 ई) के एक शिलालेख का जिक्र है। यह

शिलालेख वर्तमान में परिसर स्थित अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के प्रवेश द्वार पर लगा है। इस शिलालेख की 17वीं और 18वीं पंक्तियों में फारसी भाषा में जो दर्ज है, वह इतिहास के एक कठिन सत्य की तस्दीक करता है। एएसआई द्वारा किए गए हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है 'एक बहादुर व्यक्ति बड़ी सेना के साथ धर्म के केंद्र से इस पुराने आश्रम (मठ) में पहुंचा, उसने देवताओं की मूर्तियों को तहस-नहस कर दिया और ताकत के बल पर पूजा के स्थान को नमाज पढ़ने की जगह यानी मस्जिद में तब्दील कर दिया।'

शिलालेखों पर साहित्यिक रचनाएं- सर्वे के दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि जिन 244 शिलालेखों का अध्ययन किया गया, उनमें से कई खंड कभी बड़ी साहित्यिक रचनाओं का हिस्सा थे। इन पर नागरी लिपि में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के श्लोक अंकित हैं। इन शिलालेखों को जानबूझकर खंडित कर भवन के अलग-अलग हिस्सों में दोबारा इस्तेमाल किया गया था, ताकि उनकी मूल पहचान छुपाई जा सके। हालिया सर्वे में 50 नए शिलालेख खंड और एक खंडित प्रतिमा के आसन का टुकड़ा भी मिला है, जो इस स्थान की प्राचीन धार्मिक प्रकृति की ओर संकेत करते हैं।

शहर के कई इलाकों की हवा खराब, मेट्रो निर्माण से एक्यूआई 100 के पार

निर्माण कार्यों के कारण बढ़ रहे जहरीले कण, सेहत पर असर

इंदौर। शहर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट, फ्लायओवर निर्माण और सड़कों की खुदाई का असर अब हवा की गुणवत्ता पर साफ दिखाई देने लगा है। लगातार निर्माण गतिविधियों और धूल के कारण कई इलाकों की हवा प्रदूषित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो लोगों की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हाल के दिनों में रीगल चौराहा, एयरपोर्ट क्षेत्र और विजय नगर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 100 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो सामान्य स्तर से अधिक माना जाता है। हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले जहां मुख्य रूप से पीएम-10, कार्बन और सल्फर की मात्रा अधिक रहती थी, वहीं अब पीएम-2.5 जैसे सूक्ष्म कणों के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।

महीन कणों का स्तर अधिक- हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पीएम-2.5 की मात्रा कई स्थानों पर तय सीमा से काफी ऊपर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसका सुरक्षित स्तर 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर माना जाता है, लेकिन एयरपोर्ट क्षेत्र में यह 350 से 480 तक दर्ज किया गया। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी कई स्थानों पर तय सीमा से दोगुनी तक पाई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिन के कुछ समय में प्रदूषण का स्तर दो से तीन घंटे के लिए रेड और ऑरेंज जोन में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति लंबे समय तक रहने पर सांस से जुड़ी बीमारियां, आंखों में जलन और रक्त से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं।

छोटी ग्वालटोली क्षेत्र गंभीर- शहर में हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए आठ स्थानों पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। हालांकि इनमें से चार स्टेशन पिछले दो महीनों से तकनीकी जांच में होने के कारण नियमित आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। फिलहाल मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से रीगल क्षेत्र से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर ही शहर की हवा की स्थिति का अनुमान लगा रहा है। जहां डेटा उपलब्ध है, वहां पिछले सप्ताह के दौरान कई दिनों में एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इन दिनों मुख्य प्रदूषक के रूप में नाइट्रोजन ऑक्साइड या पीएम-2.5 सामने आया।

ऑनलाइन सिस्टम से संकेत- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन मॉनिटरिंग नेटवर्क से शहर के छह केंद्र जुड़े हुए हैं, लेकिन वेबसाइट पर नियमित रूप से केवल तीन केंद्रों का डेटा ही दिखाई देता है। उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से यह संकेत मिला है कि शहर में प्रदूषण के स्वरूप में बदलाव आ रहा है और सूक्ष्म कणों का प्रभाव पहले की तुलना में अधिक हो गया है।

एयरपोर्ट क्षेत्र में बढ़ा प्रदूषण- एयरपोर्ट क्षेत्र के आंकड़े हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले रहे हैं। 5 से 7 मार्च के बीच यहां एक्यूआई 100 से नीचे था, लेकिन 8 मार्च से इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई। 8 मार्च को एक्यूआई 148 दर्ज किया गया, 9 मार्च को 146 और 10 मार्च को यह बढ़कर 170 तक पहुंच गया। इस क्षेत्र में मेट्रो के अंडरग्राउंड निर्माण का काम लगातार चल रहा है, जिसे बढ़ते प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

कई घंटे रेड जोन- रीगल और छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में लगे मॉनिटरिंग सिस्टम के अनुसार दिन में तीन से चार घंटे तक पीएम-10 का स्तर रेड जोन में पहुंच जाता है। यहां इसका अधिकतम स्तर 265 से भी ऊपर दर्ज किया गया, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर करीब 180 तक पहुंच गया। दूसरी ओर मेघदूत पार्क क्षेत्र में औसत एक्यूआई 100 या उससे कम बना हुआ है, हालांकि यहां भी कुछ समय के लिए पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर 200 से 300 तक पहुंच जाता है। फिलहाल इस इलाके में नाइट्रोजन ऑक्साइड की स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित बताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहर में निर्माण कार्यों के दौरान धूल नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए तो प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

पुष्पा स्टाइल में हथियार घुमाने पर सख्ती

इंदौर। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील बनाकर वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर का है। यहां रहने वाले शुभम

खटीक ने गंडासे के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान कर कार्रवाई की। शुभम ने यह रील अपने घर की छत पर बनाई थी। रील में वह गंडासे के साथ गाना गाते हुए पुष्पा स्टाइल में हथियार घुमाता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इससे पहले भी शहर में इसी तरह का मामला सामने आ चुका है। तीन दिन पहले बाणगंगा इलाके के तीन युवकों की हथियार के साथ बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वे युवक इलाके में नहीं मिले। बताया जा रहा है कि वे बाहर से काम करने आए थे। सलमान लाला, भय्यू सुरीला और द्वारकापुरी का बदमाश नारू उर्फ नारायण वर्मा भी इस तरह के वीडियो वायरल कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख रही है।

शराब दुकानों की नीलामी में इंदौर अव्वल

इंदौर। शराब दुकानों की नीलामी में इंदौर संभाग सबसे आगे निकल आया है। सात संभागों में हो रही इस प्रक्रिया में इंदौर ने रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है। दूसरी ओर उज्जैन और भोपाल संभाग पीछे रह गए हैं। इंदौर संभाग से सरकार को 40 अरब रुपए के राजस्व की उम्मीद थी। अब तक यहां 25 अरब रुपए की दुकानों के सौदे हो चुके हैं, जिससे शासन को 28 अरब रुपए से अधिक की आय हो गई, यानी अनुमान से 3 अरब रुपए ज्यादा राशि मिली है। मंगलवार को दो और ग्रुप के सौदे होने के बाद यहां 70 प्रतिशत दुकानों की बिक्री पूरी हो चुकी है। उज्जैन संभाग में 26 अरब रुपए के राजस्व का अनुमान था, लेकिन अब तक सिर्फ 6 अरब रुपए की दुकानों के सौदे हो पाए हैं। ऊंची कीमतों के कारण कई दुकानें बेस प्राइस पर ही जा रही है और कई जगह खरीदार नहीं मिल रहे। भोपाल संभाग में प्रतिस्पर्धा नहीं दिखी। यहां 37 अरब रुपए से अधिक के राजस्व की संभावना थी, लेकिन 10 अरब रुपए की ही बिक्री हो सकी। कुल दुकानों में से 28 प्रतिशत ही बिक सकी। सागर-ग्वालियर संभाग का प्रदर्शन ठीक रहा है। रीवा संभाग ने बेहतर प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। यहां 9 अरब रुपए से ज्यादा की दुकानों के सौदे हो चुके हैं और 2 अरब रुपए अतिरिक्त कीमत मिली है।

पत्नी पर चरित्र शंका में जानलेवा हमला

इंदौर। चरित्र शंका में पत्नी पर दराते से प्राणघातक हमला करने वाले पति को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। चंदन नगर पुलिस को 9 मार्च की देररात जिला अस्पताल से सूचना मिली थी कि लक्ष्मी पति सुभाष उईके निवासी व्यास नगर को घायल अवस्था में लाया गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। यहां घायल महिला की चचेरी बहन मनीषा ने बताया कि वह उसके पड़ोस में निवास करती है। सुभाष को शंका थी कि उसकी पत्नी का किसी ओर युवक से संबंध है। इसे लेकर दोनों में विवाद होते रहते थे। घटना वाले दिन महिला का पति से विवाद हुआ था। इसके बाद उसने हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिला धारा 109 का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी को पकड़ने टीम गठित की थी। टीम ने मशक्कत के बाद पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी मजदूरी और झाड़ू पोरा करती है। उसे संदेह था कि उसका किसी ओर से भी प्रेम प्रसंग है और वह दूसरे युवक से बात करती है। इसलिए शंका के आधार पर वारदात की।

बेहतर पुलिस ड्यूटी करने वाले सम्मानित

इंदौर। हाल ही में होलिका दहन, होली, रंगपंचमी, गेर और टी-20 मैच में जीत के बाद निकले जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बुधवार को पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी ने थाना महू के ड्यूटी पर तैनात स्टाफ, पुलिस लाइन ग्रामीण में पदस्थ निरीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय के कर्मचारियों और महू के एनआरएस सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने सभी की हौसला अफजाई कर उनके कार्य की सराहना की। इस दौरान थाना महू के 37 अधिकारी-कर्मचारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 5 कर्मचारी, पुलिस लाइन ग्रामीण के 2 निरीक्षक, 123 बीएन के 9 अधिकारी-कर्मचारी और एनआरएस महू के 7 सदस्यों को सम्मानित किया गया।

विवाह आयोजन की तारीख बढ़ाई

कमर्शियल गैस टंकी को लेकर संकट खड़ा हो गया है। संकट का असर वैवाहिक आयोजनों पर भी पड़ने लगा है। मंगलवार को आयोजक यादव और लोधी समाज ने एमआर 10 के समीप एक धर्मशाला में विवाह समारोह की पार्टी तारीख आगे बढ़ा दी है। दोनों समारोह में पार्टियां 15 और 17 मार्च होना थी। लेकिन टंकी नहीं मिलने की जानकारी से पार्टियां निरस्त की है। संकट खत्म होने के बाद पार्टियां देने की नई तारीख तय होगी।

होस्टल चलाने के लिए 20 हजार मांगे

इंदौर। बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे अब होस्टल चलाने के नाम पर रंगदारी दिखा रहे हैं। संचालक से इसके लिए 20 हजार रुपए की मांग की। पैसा देने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की। भंवरकुआं पुलिस के मुताबिक, घटना भोलाराम उस्ताद मार्ग की है। फरियादी अनिरुद्ध पिता आशीष जोशी निवासी महल कचहरी ने बताया कि वह अपने होस्टल के काम से भोलाराम मार्ग पर खड़ा था। तभी वहां आरोपी मिलन नागर निवासी श्रीयंत्र नगर आया और धमकाते हुए बोला कि अगर होस्टल चलाना है तो हर महीने 20 हजार रुपए देने पड़ेंगे। मेरे द्वारा मना करने पर मारपीट की गई।

शराबी बेटे ने पिता को डंडे से पीटा

इन्दौर। मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकने पर कलयुगी बेटे ने पिता को डंडे से पीट दिया। लसूड़िया पुलिस ने फरियादी राजेंद्र शर्मा की शिकायत पर उनके बेटे नंदकिशोर के खिलाफ दर्ज किया गया है। राजेंद्र ने बताया कि उनका बेटा शराब पीने का आदी है। घर में अक्सर विवाद करता रहता है। बेटा अक्सर मेरा मोबाइल छीन लेता है और देर रात तक उसका इस्तेमाल करता रहता है। 10 मार्च को मैंने उसे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने और समय बर्बाद न करने की सलाह दी तो वह भड़क गया। फिर मुझे गालियां देने लगा। मना किया तो हमला कर दिया।

बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान

इंदौर। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस कमिश्नर के मार्गदर्शन में सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत का संचालन किया जा रहा है। इस पहल के तहत बुजुर्गों की शिकायतों को सुनकर उनका निराकरण किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया के निर्देशन में हर बुधवार को काउंसलिंग की जाती है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उन्हें हल करने का प्रयास किया जाता है। इस क्रम में काउंसलिंग टीम के सदस्य डॉ आरडी यादव, पुरुषोत्तम यादव, रमेश शर्मा को कई प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 5 मामलों का समाधान किया। जबकि अन्य मामलों में सुनवाई कर अगली तारीख तय की गई है। पुलिस ने बताया कि बुजुर्गों की समस्या समाधान के लिए रीगल चौराहा स्थित नगर पुलिस सुरक्षा समिति कार्यालय में रोज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आवेदन लिए जाते हैं। इसके बाद सीनियर सिटीजन और संबंधित पक्षों को बुलाकर आपसी बातचीत और काउंसलिंग से समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है।

संपादकीय

विपक्ष का मकसद पूरा हुआ ?

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का खारिज होना तो पहले से तय था, क्योंकि उसके पास संख्याबल नहीं था, लेकिन यह प्रस्ताव लाकर विपक्ष यह संदेश देने में जरूर कामयाब रहा कि सदन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष की गंभीरता का संकेत तो तभी मिल गया था, जब इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भी नहीं बोले। ऐसे में सवाल यह उठा कि अगर उन्हें सदन में इस मुद्दे पर कुछ बोलना ही नहीं था तो फिर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का असल उद्देश्य क्या था? क्या वो सिर्फ यह जताना चाहते थे कि सदन में उन्हें वो नहीं बोलने नहीं दिया गया, जो बोलना चाहते थे या फिर उनका मतंव्य स्पीकर को पक्षपाती साबित करना था? यदि करना भी था तो सदन में वो अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते थे। मान सकते हैं कि स्पीकर ने सदन में राहुल गांधी को वो बात नहीं रखने दी, जो वो रखना चाहते थे, लेकिन यह भी सही है कि सदन में कोई भी बात नियमबाह्य तरीके से नहीं रखी जा सकती। करीब 119 विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि स्पीकर सदन चलाते समय पक्षपात कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा। हालांकि मंत्री अमित शाह ने यह कहकर विपक्ष की चुटकी ली कि स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, उसमें भी गलतियां थीं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आचरण और मंशा पर तगड़े प्रहार किए। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश भी की कि जब भी लोकसभा में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, वो देश के बाहर ही रहते हैं। 56 मिनट के अपने भाषण में शाह ने साफ कहा कि राहुल की यह शिकायत बेमानी है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, हकीकत यह है कि वो बोलना ही नहीं चाहते, ऐसे में कोई क्या कर सकता है। शाह ने यह भी कहा कि सदन में कोई भी बात नियमों के तहत ही रखी जा सकती है। संसद को चौराहे की सभा नहीं है। अगर राहुल गांधी को नियमों का ज्ञान नहीं है तो वे अपने वरिष्ठ साथियों से इसकी जानकारी ले लें। शाह ने कहा कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसदों को बोलने के लिए भाजपा से दो गुना ज्यादा समय मिला। फिर भी विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हम भी बरसों विपक्ष में रहे, लेकिन कभी स्पीकर की मंशा और आचरण पर सवाल नहीं उठाया और नही कभी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। अपने लंबे और मारक भाषण में शाह ने राहुल गांधी को लक्ष्य कर टिप्पणी की कि आंख मारने वाले आज स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन में शाह माफी मांगों के नारे लगने लगे। हंगामे के बीच सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर मत विभाजन की मांग नहीं की। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 10 घंटे तक बहस चली। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद लोकसभा स्पीकर ने नैतिक आधार पर लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं की। इस दौरान सदन की कार्यवाही सभापति ही चलाते रहे। अब प्रस्ताव खारिज होने के बाद बिरला सदन की कार्वयाही की फिर से अध्यक्षता कर सकते हैं।

पश्चिमी यूपी में उम्मीद से भरी सपा की चुनावी तैयारी

2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहा था। पश्चिमी यूपी में कुल मिलाकर करीब 136 विधानसभा सीटें आती हैं जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़ और आसपास के जिले शामिल हैं। 2022 में इस पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी को केवल 35 से 38 के आसपास सीटें मिली थीं जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां करीब 80 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो पश्चिमी यूपी में भाजपा को करीब 44 से 46 फीसदी वोट मिले थे जबकि सपा 30 से 33 फीसदी के आसपास सिमट गई थी। राष्ट्रीय लोकदल उस वक्त सपा के साथ गठबंधन में था और उसने जाट बहुल इलाकों में कुछ सीटें जिताई थीं, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन का समग्र प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले कमजोर ही रहा।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं।

समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में समानता भाईचारा रैली के जरिए अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे। यह महज एक रैली नहीं है, बल्कि यह उस बड़ी राजनीतिक योजना की शुरुआत है जिसके जरिए अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जमीन को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। दादरी का चुनाव भी रणनीतिक है क्योंकि यह इलाका जाट, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों की मिली-जुली आबादी वाला क्षेत्र है और यहीं से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को धार देने की कोशिश की जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहा था। पश्चिमी यूपी में कुल मिलाकर करीब 136 विधानसभा सीटें आती हैं जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़ और आसपास के जिले शामिल हैं। 2022 में इस पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी को केवल 35 से 38 के आसपास सीटें मिली थीं जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां करीब 80 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। वोट प्रतिशत की बात करें तो पश्चिमी यूपी में भाजपा को करीब 44 से 46 फीसदी वोट मिले थे जबकि सपा 30 से 33 फीसदी के आसपास सिमट गई थी। राष्ट्रीय लोकदल उस वक्त सपा के साथ गठबंधन में था और उसने जाट बहुल इलाकों में कुछ सीटें जिताई थीं, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन का समग्र प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले कमजोर ही रहा।

पश्चिमी यूपी में सपा की कमजोरी की जड़ें बहुत गहरी हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस इलाके में जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच जो दरार पैदा हुई थी, उसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। जाट मतदाता जो परंपरागत रूप से कभी कांग्रेस तो कभी लोकदल के साथ रहते थे, 2014 के बाद से भाजपा की तरफ मजबूती से झुक गए। 2022 में भी यह झुकाव बड़े पैमाने पर बना रहा। हालांकि राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन के बाद यह उम्मीद जगी थी कि जाट वापस भाजपा से नाराज होंगे, लेकिन वोटिंग के वक्त बड़े पैमाने पर यह नाराजगी सपा के पक्ष में नहीं बदल पाई। अब 2023 में राष्ट्रीय लोकदल ने सपा का साथ

छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि 2027 में सपा के पास पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं तक पहुंचने का वह पुराना पुल नहीं रहेगा। पश्चिमी यूपी की करीब 40 से 45 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन सीटों पर रालोद के भाजपा के साथ जाने से सपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।ऐसे में अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति ही वह हथियार है जिससे वे इस गणित को पलटना चाहते हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का यह फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी हद तक काम भी किया। 2024 में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतीं जो पार्टी के इतिहास में लोकसभा का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। पश्चिमी यूपी में भी 2024 में सपा ने कुछ अप्रत्याशित जीतें दर्ज कीं। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में सपा और उसके सहयोगी दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इससे अखिलेश को भरोसा मिला कि पीडीए का फार्मूला अगर सही तरीके से जमीन पर उतारा जाए तो पश्चिमी यूपी में भी बड़ा बदलाव संभव है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जातीय संरचना पर गौर करें तो यहां मुस्लिम आबादी कई जिलों में 30 से 40 फीसदी तक है। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और वे परंपरागत रूप से सपा के साथ रहे हैं। इसके अलावा दलित मतदाता जो अनुसूचित जाति के हैं, पश्चिमी यूपी में करीब 20 से 22 फीसदी हैं। पिछड़े वर्ग जिनमें यादव, कुर्मी, सैनी, प्रजापति, गुर्जर और अन्य जातियां शामिल हैं, उनकी भी पश्चिमी यूपी में ठीकठाक मौजूदगी है। अगर ये तीनों तबके एकजुट होकर सपा को वोट दें तो कम से कम 50 से 55 फीसदी वोट का आधार बन सकता है जो किसी भी सीट पर जीत के लिए पर्याप्त है।लेकिन असली चुनौती इन्हें एकजुट करना है। दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखता है। हालांकि मायावती की पार्टी 2022 और 2024 दोनों चुनावों में बुरी तरह पिटी है और उनका वोट बैंक बिखर रहा है। अखिलेश की कोशिश है कि इस बिखरे हुए दलित वोट को अपनी तरफ खींचा जाए। दादरी की रैली में समानता और भाईचारे का संदेश इसीलिए दिया जाएगा ताकि दलित समुदाय को यह भरोसा दिलाया जा सके कि सपा उनकी पार्टी है।

पश्चिमी यूपी में सपा के सामने एक और बड़ी समस्या संगठन की है। इस इलाके में सपा का जमीनी ढांचा बहुत मजबूत नहीं है। पूर्वी यूपी के मुकाबले जहां यादव बाहुल्य क्षेत्र हैं और पार्टी की गहरी जड़ें हैं, पश्चिमी यूपी में सपा को हर बूथ तक अपनी पहुंच बनाने के लिए नए सिरे से काम करना होगा। अखिलेश ने इसके लिए रैलियों और जनसंपर्क अभियानों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की है जो दादरी से शुरू होकर पूरे पश्चिमी यूपी को कवर करेगी।भाजपा के लिए भी यह लड़ाई आसान नहीं होगी। किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे जनता के मन में हैं। पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों का बकाया और सरकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन बड़े सवाल हैं। सपा इन्हीं मुद्दों को हवा देकर अपना रास्ता बनाना चाहती है। 2027 में पश्चिमी यूपी की लड़ाई तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का रुख किस तरफ जाएगा। इस इलाके की 136 के करीब सीटें किसी भी दल को सरकार बनाने या रोकने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर पश्चिमी यूपी नहीं जीता तो लखनऊ की राह बंद है। दादरी की रैली इसी लंबे सफर का पहला कदम है।

डिजिटल फुटप्रिंट और इको चैंबर में फंसते हम लोग

विचार

मनीष जैसल

लेखक मीडिया प्रोफेसर हैं।

इक्कीसवीं सदी के आरंभिक दशकों में मानव सभ्यता ने जिस तीव्रता से डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाया है, उसने संचार, राजनीति, व्यापार और सामाजिक जीवन की संरचना को मूलतः बदल दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने सूचना तक पहुँच को पहले से कहीं अधिक सरल और तेज बना दिया है। लेकिन इसी परिवर्तन के भीतर एक ऐसी जटिल प्रक्रिया भी विकसित हुई है, जिसने विचारों की स्वतंत्रता और सामाजिक संवाद की प्रकृति पर नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

डिजिटल दुनिया में मनुष्य केवल सूचना का उपभोक्ता नहीं रह गया है; वह स्वयं भी सूचना का उत्पादक और डेटा का स्रोत बन गया है। हम प्रतिदिन इंटरनेट पर जो कुछ भी करते हैं जिस किसी विषय को खोजते हैं, किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, किसी वीडियो को देखते हैं, किसी लिंक को साझा करते हैं, सभी गतिविधियों का एक स्थायी रिकॉर्ड बनता जाता है। इस रिकॉर्ड को ही डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। यह हमारे विचारों, रुचियों, सामाजिक संबंधों और व्यवहारिक पैटर्न का विस्तृत डिजिटल अभिलेख बन जाता है। समय के साथ यह डेटा इतना विस्तृत हो जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे व्यवहार और पसंद का अनुमान लगाने लगते हैं।

इसी प्रक्रिया के समानांतर एक और महत्वपूर्ण संचारिक परिघटना विकसित होती है, वह है इको चैंबर। इको चैंबर वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगातार वही विचार और सूचनाएँ दिखाई देती हैं जिनसे वह पहले से सहमत होता है। धीरे-धीरे उसका सूचना-परिसर सीमित होता जाता है और वह विविध विचारों से दूर होने लगता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिद्म इस प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं। इन एल्गोरिद्म का उद्देश्य उपयोगकर्ता को अधिक समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना होता है। इसलिए वे वही सामग्री अधिक दिखाते हैं जिस पर उपयोगकर्ता पहले से प्रतिक्रिया देता रहा है।

यह सुविधा धीरे-धीरे विचारों की सीमा में बदल सकती है। व्यक्ति को लगता है कि उसकी राय ही बहुसंख्यक समाज की राय है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में उसे उसी प्रकार की सामग्री अधिक दिखाई देती है। यही स्थिति इको चैंबर की मूल विशेषता है।

डिजिटल इको चैंबर और गलत सूचना के प्रसार को लेकर हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अध्ययन सामने आए हैं। वर्ष 2018 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के शोधकर्ताओं सिनान अराल (Sinan Aral), देब राय (Deb Roy) और सोरूश वोज़ी (Soroush Vosoughi) द्वारा किया गया एक विस्तृत अध्ययन पत्रिका Science में प्रकाशित हुआ। इस शोध में 2006 से 2017 के बीच ट्विटर पर प्रसारित लगभग 1,26,000 समाचार कथाओं और लगभग 30 लाख उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन का निष्कर्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण था, झूठी खबरें सही खबरों की तुलना में लगभग छह गुना अधिक तेजी से और अधिक व्यापक रूप से फैलती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि सनसनीखेज और भावनात्मक सामग्री लोगों को अधिक आकर्षित करती है, इसलिए एल्गोरिद्मिक प्लेटफॉर्म पर वह अधिक तेजी से साझा होती है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर फिलिप एन. हावर्ड और उनकी टीम ने 2019 में प्रकाशित अपने अध्ययन में बताया कि संगठित डिजिटल नेटवर्क और एल्गोरिद्मिक अनुशंसाएँ कई बार उपयोगकर्ताओं को समान विचारों वाले समूहों में सीमित कर देती हैं। इस प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म अनजाने में ऐसे सूचना-परिसर निर्मित कर देते हैं जहाँ व्यक्ति अपने ही विचारों की प्रतिध्वनि अधिक सुनता है और विविध दृष्टिकोणों से उसका संपर्क धीरे-धीरे कम हो जाता है। यही वह प्रक्रिया है जो आधुनिक डिजिटल समाज में इको चैंबर की समस्या को और अधिक गहरा करती जा रही है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार लगभग 8.7 करोड़ फेसबुक उपयोगकर्ताओं की जानकारी इस प्रक्रिया में शामिल थी। इस डेटा में उपयोगकर्ताओं की लाइक्स, सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन गतिविधियाँ और व्यवहारिक पैटर्न शामिल थे।

इन सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का एक विस्तृत मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार किया गया। इसके बाद मतदाताओं को लक्षित संदेश भेजे गए। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपयोगकर्ता का डिजिटल व्यवहार यह संकेत देता था कि वह सुरक्षा या प्रवासन जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित है, तो उसे उसी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन दिखाए जाते थे। इस रणनीति को माइक्रो-टार्गेटिंग कहा जाता है। इसमें व्यापक जनसमूह को एक समान संदेश देने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग संदेश भेजे जाते हैं। डिजिटल इको चैंबर का एक गंभीर उदाहरण म्यांमार में रोहिंग्या संकट के दौरान सामने आया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में उल्लेख किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग इस संघर्ष के दौरान घृणा फैलाने वाली सामग्री के प्रसार के लिए किया गया। म्यांमार में बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ता फेसबुक को ही इंटरनेट का मुख्य माध्यम मानते थे। इस स्थिति में जब कुछ संगठित समूहों ने रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध भ्रामक और उकसाने वाले संदेश फैलाने शुरू किए, तो एल्गोरिद्म ने उन संदेशों को तेजी से अधिक लोगों तक पहुँचा दिया। एल्गोरिद्म का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि जिस सामग्री पर अधिक प्रतिक्रिया मिलती है, उसे अधिक लोगों तक पहुँचाया जाता है। दुर्भाग्य से नफरत और सनसनीखेज संदेश अक्सर अधिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करते हैं। ऐसे संदेश व्यापक रूप से फैलने लगे और एक ऐसा डिजिटल वातावरण तैयार हुआ जिसमें एक ही प्रकार की जानकारी बार-बार दिखाई देने लगी। इस प्रक्रिया ने सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया और वास्तविक दुनिया में हिंसा की स्थितियों को भी प्रभावित किया।

कोविड-19 महामारी ने डिजिटल सूचना व्यवस्था की एक और जटिल चुनौती को सामने रखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति को 'इन्फोडेमिक' कहा– अर्थात ऐसी सूचना महामारी जिसमें गलत और भ्रामक जानकारी अत्यंत तेजी से फैलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरस की उत्पत्ति, उपचार और वैक्सीन को लेकर अनेक प्रकार के दावे प्रसारित होने लगे। कई उपयोगकर्ताओं का डिजिटल फुटप्रिंट पहले से ही ऐसे समूहों से जुड़ा हुआ था जो वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास व्यक्त करते थे। एल्गोरिद्म ने इन्हीं उपयोगकर्ताओं को समान विचारधारा वाली सामग्री अधिक दिखानी शुरू कर दी। परिणामस्वरूप, कुछ समुदायों में वैक्सीन के प्रति संदेह और भ्रम तेजी से बढ़ने लगा। स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और अन्य शोध संस्थानों के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि जब व्यक्ति लगातार एक ही प्रकार की जानकारी देखता है, तो उसकी धारणा अधिक कठोर हो जाती है और वह विरोधी विचारों को कम विश्वसनीय मानने लगता है।

6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) पर हुआ हमला डिजिटल इको चैंबर के प्रभाव का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इस घटना से पहले कई महीनों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव परिणामों को लेकर विभिन्न दावे और षड्यंत्र सिद्धांत प्रसारित होते रहे। एल्गोरिद्म ने उन उपयोगकर्ताओं को एक-दूसरे से जोड़ दिया जिनका डिजिटल व्यवहार पहले से ही ऐसे विचारों से जुड़ा हुआ था।

धीरे-धीरे एक ऐसा डिजिटल समुदाय तैयार हो गया जिसमें चुनावी प्रक्रिया के प्रति अविश्वास का भाव लगातार मजबूत होता गया। संचार अध्ययन में इस प्रक्रिया को कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है–अर्थात व्यक्ति वही सूचना स्वीकार करता है जो उसके पहले से बने विश्वास को पुष्ट करती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिक पारदर्शी हों और उपयोगकर्ता भी सूचना के प्रति अधिक सजग बनें। कई देशों में डेटा सुरक्षा कानून और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही शिक्षा और मीडिया संस्थानों में डिजिटल साक्षरता पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल तकनीक का उपयोग करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि एल्गोरिद्म किस प्रकार सूचना का चयन करते हैं और उपयोगकर्ता किस प्रकार विविध स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल युग ने मानव समाज को अभूतपूर्व सूचना-समृद्धि प्रदान की है, लेकिन इसके साथ कुछ नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। डिजिटल फुटप्रिंट और इको चैंबर ऐसी ही दो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जो आधुनिक समाज की सूचना संरचना को प्रभावित कर रही हैं। यदि डिजिटल दुनिया हमें केवल हमारे ही विचारों की प्रतिध्वनि सुनाने लगे, तो सूचना की समृद्धि धीरे-धीरे विचारों की संकीर्णता में बदल सकती है। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ विचारों की खुली और संतुलित दुनिया को भी सुरक्षित रखा जाए।

किस्सा-ए-अंकल सैम और मरहूम मासूम बच्चियाँ

वक्रोक्ति

शांतिलाल जैन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

आदाब, नमस्कार। खुशामदीद ख़वातीन-ओ-हज़रात। सुनो सुनो। सात समंदर पार का दर्दनाक किस्सा सुनो। चश्म-ए-नम कर देने वाला किस्सा सुनो। दिल चीर देने वाला किस्सा सुनो। सीना चाक न कर दे तो नाम बदल देना किस्सागो का।

यूँ तो सुने आपने अब तक किस्से बादशाहों के, शहंशाहों के, राजाओं के, महाराजाओं के, निज़ाम के, सियासी रहनुमाओं के। आज सुनिए आप किस्सा-ए-अंकल सैम और मरहूम मासूम बच्चियाँ। एक रहे आए अंकल सैम, पढ़े लिखे अंकल सैम! सभ्य अंकल सैम! समृद्ध अंकल सैम! दुनिया के चौधरी अंकल सैम! फ़ारस का निज़ाम बदलवाने निकले अंकल सैम! असली मकसद तो तेल बेचना। तेल बेचने निकले अंकल सैम! तेल कब्ज़ाने निकले अंकल सैम! तेली नंबर-वन का मिशन लिए निकले अंकल सैम! क्रूर अंकल सैम! लालच में अंधे अंकल सैम! ख़वातीनों को आज़ाद कराने निकले, एक सौ पैंसठ बच्चियों को फ़ानी दुनिया से आज़ाद करा बैठे।

वो कैसे किस्सागो?

ख़ल्क़ खुदा का, मुल्क अंकल सैम का, हुक्म ट्रंप साहेब का। हुक्म टॉमहॉक मिसाईल चलाने का। चली मिसाईल तो गिरी जाकर मिनाब शहर के इलेमेंट्री स्कूल पर। अल्लाह को प्यारी हो गईं डेढ़ सैंकड़ा बच्चियाँ। न डॉलर जानती थीं न पेट्रो डॉलर। न टैरिफ न बेलेंस ऑफ़ पेमेंट। मरहूम बच्चियाँ। मासूम बच्चियाँ। अम्मी-अब्बू की उम्मीदों की बच्चियाँ। उनकी अँखियों की नूर बच्चियाँ। टूटे ख्वाबों की बच्चियाँ। उनके ख्वाबों में तालीम थी। ख्वाब टीचर बनने के। ख्वाब डॉक्टर बनने के। ख्वाब साइंटिस्ट बनने के। अम्मी जैसा घर बसाने के ख्वाब। अपने हिस्से की आधी दुनिया को खूबसूरत बनाने के ख्वाब। अंकल सैम की नफ़रत, हिंसा और क्रूरता से चूर चूर ख्वाब।

ख़वातीन-ओ-हज़रात, बच्चियों से पुरानी दुश्मनी रही आई अंकल सैम की। एक्जोटिक आईलेंड पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ मुँह काला करके आए थे, छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल पर मिसाईल दाग बैठे। चले थे शांति का नोबेल लेने, अबोध बालिकाओं का वध कर बैठे। मस्ती के मंज़र एपस्टीन की फाईल में, तबाही का मंज़र स्कूल के दालान में। अधजले दुपट्टे, अधखाए लंच बॉक्स, बिखरे स्कूल बेग, बिखरी पॉकेट मनी, खून से लथपथ होमवर्क की कॉपियाँ, कॉपियों में यहाँ वहाँ चितरी बे-तरतीब ड्राईंग, गुस्सैल टीचर के मुँह चिढ़ाते रेखाचित्र, जुगराफियों के तितर-बितर नक़्शे, नक्शों पर खीचीं सरहदें बदलने की ज़िद में चली टॉमहॉक मिसाईल। काँप उठी कायनात, बच्चियों की चीख से नहीं, खामोश जन्नत नशींनी से।

हाँ तो ख़वातीन-ओ-हज़रात, इसके बाद किस्से में रह ही क्या जाता है। जंग जारी है। जंग के किस्से ख़त्म नहीं होते। रुंध जाए गला किस्सागो का तो किस्से को विराम लेना ही होता है। अलविदा।

अरे! रुको रुको किस्सागो, चश्म-ए-नम तो हमारी भी हैं मगर इतना तो बताते जाओ उसी समय जंबूद्वीप में क्या हुआ?

कुछ नहीं हुआ ख़वातीन-ओ-हज़रात। एक होर्डिंग खड़ा था वहाँ, अपने सीने पर बड़े बड़े हर्फ़ों में एक जागतिक नारा चस्पाँ किए - 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। होर्डिंग ख़ामोश खड़ा रहा। होर्डिंग अब भी ख़ामोश है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

समाधि की नई विधि: स्क्रीन पर झुकी हुई गर्दन

व्यंग्य

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हमारे देश में महापुरुषों की परंपरा सदियों पुरानी रही है। कभी महात्मा बनने के लिए घर-द्वार छोड़कर जंगलों में तपस्या करनी पड़ती थी; वर्षों साधना के बाद कहीं ज्ञान की झलक मिलती थी। पर आधुनिक युग ने यह साधना सरल कर दी है। पहले ऋषि-मुनि पीपल या बरगद के नीचे समाधि लगाते थे, आज लोग बस स्टैंड, चौराहों और बाजारों के बीच मोबाइल में ऐसी तल्लीनता से डूब जाते हैं कि आसपास की दुनिया जैसे मिट जाती है। सामने से ट्रक निकल जाए या कोई पुकारता रह जाए–ध्यान टस से मस नहीं होता। इतनी अडिग एकाग्रता योगशास्त्रों में भी दुर्लभ है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भविष्य में योग की नई विधा जन्म लेगी– 'मोबाइल योग', जिसमें साधक अंगूठे के आसन में बैठकर ज्ञान प्राप्त करेगा।

पहले मनुष्य की सुबह बड़ी पवित्र होती थी। लोग उठते ही जल पीते, सूर्य को प्रणाम करते और ईश्वर का स्मरण करते थे। अब सुबह का पहला संस्कार बदल गया है– आँख खुलते ही हाथ मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। उसे जानने की उत्सुकता रहती है कि रात भर में दुनिया ने उसके बारे में क्या सोचा, किसने उसकी तस्वीर पर मुस्कान भेजी और किसने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ संदेश मिल जाएँ तो मन प्रसन्न हो जाता है, और न मिलें तो लगता है जैसे संसार ने उपेक्षा कर दी हो। प्रार्थना में धैर्य चाहिए, पर मोबाइल में प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है; इसलिए आज का मनुष्य धैर्य की साधना छोड़कर प्रतिक्रिया के प्रसाद से ही संतुष्ट हो जाता है।

एक सुबह मैंने देखा कि पड़ोसी मोबाइल में इतनी गहरी डूबे हैं कि मानो कोई पुराना ग्रंथ पढ़ रहे हों। मैं हँसते हुए पूछ बैठा, 'क्यों, नया शोध कर रहे हो?' उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, 'देश-दुनिया की हलचल पढ़ रहा हूँ।' मैंने कहा, 'इतनी हलचल जानने से क्या फायदा?' वे मुस्कुराए और बोले, 'दुनिया सुधरे या न सुधरे, कम से कम मन को संतोष मिलता है–हर जगह गड़बड़ी बराबर है।' तभी मुझे लगा, मोबाइल ने हमारे दृष्टिकोण को ही बदल दिया है–दूसरों की उलझनों को देखकर अपनी परेशानियाँ हल्की लगने लगती हैं। पहले लोग संतों के प्रवचन सुनकर संतोष पाते थे, अब सोशल मीडिया देखकर। मोबाइल ने समाज को ज्ञानियों से भर दिया है। पहले किसी विषय पर राय देने से पहले लोग झिझकते थे, डर रहता था कि कहीं कोई सचमुच का जानकार सामने न आ जाए। अब यह डर खत्म हो गया है। एक दिन मैंने देखा कि एक सज्जन बड़े आत्मविश्वास से अपने विचारों की जादुई गंगा बहा रहे थे। मैंने पूछा, 'यह सब अनुभव कहाँ से आते हैं?' वे मुस्कुराए और बोले, 'अनुभव तो थोड़ा-बहुत है, बाकी सब मोबाइल की ताकत है–जब हाथ में यह है, तो सोच की कोई सीमा नहीं रहती।' मुझे लगा, मोबाइल ने लोकतंत्र को इतना व्यापक बना दिया है कि हर नागरिक अपने आप में चलता-फिरता नीति आयोग बन गया है। घर-परिवार के जीवन में भी मोबाइल ने अद्भुत शांति ला दी है। पहले शाम को लोग आँगन में बैठकर दिनभर की बातें और हँसी-मज़ाक करते थे। अब दृश्य ऐसा है मानो चार साधक मौन साधना कर रहे हों–सभी के सिर झुके और उंगलियाँ स्क्रीन पर चलती रहती हैं। बच्चे पहले दादी से कहानियाँ सुनते थे, अब छोटी-छोटी वीडियो से ज्ञान ले लेते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, 'बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?' उसने कहा, 'इन्फ्लुएंसर।' मैंने पूछा, 'यह कैसा पेशा है?' उसने कहा, 'जहाँ खुद कम मेहनत करते हैं, पर दूसरों को बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए।' लगा, पुरानी परंपरा अब बस नया नाम पा गई है। रिश्तों पर भी मोबाइल का बड़ा असर हुआ है। पहले हाल पूछने घर जाना पड़ता था, अब तस्वीर देखकर ही समझ लिया जाता है कि सामने वाला खुश है या दुखी। शादी हो जाए तो पहला सवाल: 'फोटो भेजना'–जैसे यही शादी की असली पुष्टि हो। एक बार परिचित अस्पताल में एडमिट थे। मित्र उससे मिलने आए, लेकिन अधिक समय मोबाइल कैमरे का कोण ठीक करने में लगा। एक ने कहा, 'चेहरा सीधा करो, तस्वीर साफ आएगी।' परिचित बोले, 'भाई, तकलीफ हो रही है।' मित्र ने कहा, 'तकलीफ तो रहेगी, पर फोटो अच्छी होनी चाहिए।' तभी मुझे लगा, आधुनिक संवेदना का अर्थ है–दुख में भी फ्रेम सही होना चाहिए।

मोबाइल ने मनुष्य को अद्भुत स्वतंत्रता दी है–बिना मेहनत के महान बनने की। अब कोई घर बैठे समाज सुधारक, देशभक्त या दार्शनिक बन सकता है; बस कुछ तीखी टिप्पणियाँ लिखिए और आत्मसंतोष मिल जाता है। मैंने देखा एक युवक दिन भर प्रेरक वीडियो देख रहा था। मैंने पूछा, 'तुम खुद क्या कर रहे हो?' बोला, 'मैं तो बस सीख रहा हूँ, असली फैसला तो डिजिटल दुनिया करेगी।' लगा, अगर पुराने संत आज होते तो तपस्या के लिए पहाड़ नहीं, बल्कि अच्छी सिग्नल वाली जगह चुनते। ज्ञान अब शायद पेड़ के नीचे नहीं, मोबाइल टॉवर की छाया में मिलता। और सच यही है–मोबाइल ने दुनिया से तो जोड़ा, पर सोचने की आदत छीन ली; अब असली साहस है, स्क्रीन बंद कर खुद को आज़माना।

नाना फड़नवीस : मराठा कूटनीति का चाणक्य

पुण्यतिथि पर विशेष लेख

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शिक्षक एवं शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।

नाना फड़नवीस का जन्म सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में प्रवाहित कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित मराठा शक्ति केन्द्र सतारा में 13 फरवरी, 1742 को हुआ था। इनका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, किंतु नाना फड़नवीस के नाम से कीर्ति पताका अद्यावधि फहर रही है। छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा नियुक्त किया जो 1720 तक पदासीन रहे। नाना फड़नवीस के दादा बालाजी महादजी भानु पेशवा के मित्र और मराठा साम्राज्य सेवा में कार्यरत थे। मुगलों द्वारा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हत्या की रची गई साज़िश का पर्दाफाश कर पेशवा की प्राण रक्षा करने पर नाना फड़नवीस के दादा को फड़नवीस की उपाधि प्रदान की गई थी, जो आगे चलकर उनके वंश की पहचान बन गई। 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम पेशवा रहे, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारे और मराठा साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया। 1740 से 1761 तक बालाजी बाजीराव पेशवा का कार्यकाल रहा, जिनके सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। नाना फड़नवीस इन्हीं सदाशिवराव भाऊ के सचिव थे।

मराठा साम्राज्य का संदर्भ आते ही आंखों के सम्मुख छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि उभरती है, जिन्होंने मुगलों के काल में भारत में मराठा साम्राज्य को न केवल एक शक्ति के रूप में स्थापित किया बल्कि राजनीति, कूटनीति, प्रशासन एवं युद्धशैली को नवल अर्थ भी दिए। किंतु शिवाजी महाराज के अवसान के पश्चात् सुयोग्य एवं दूरदर्शी नेतृत्व के अभाव में मराठा शक्ति क्षीणतर होती गई और राज्य संचालन एवं प्रशासन के सूत्र पेशवा (प्रधानमंत्री) के हाथों में स्थानांतरित होते गये। छत्रपति शाहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को प्रथम पेशवा (प्रधानमंत्री) के रूप में नामित किया था। छत्रपति शाहूजी महाराज के द्वारा मनोनीत पेशवा पद वंशानुगत हो गया और कालांतर में पेशवा ही मराठा शासक के रूप में स्थापित हो गये। नाना फडनवीस पेशवा के अधीन एक राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ के साथ ही कुशल युद्धनीतिज्ञ, दूरदर्शी, स्वामिभक्त, चतुर प्रशासक और मराठा साम्राज्य के हितैषी थे। उन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध की पराजय से बिखरी मराठा सैन्य शक्ति, कमजोर आर्थिक स्थिति और निरंकुश प्रशासन को अपनी कार्य कुशलता से पुनः स्थापित किया। इतिहासकारों ने नाना फड़नवीस को मराठा साम्राज्य का चाणक्य और मैकियावेली कहा। वह निःस्वार्थ सेवा-साधना, समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के अनुपम उदाहरण बन गये।

नाना फड़नवीस का जन्म सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में प्रवाहित कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित मराठा शक्ति केन्द्र सतारा में 13 फरवरी, 1742 को हुआ था। इनका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, किंतु नाना फड़नवीस के नाम से कीर्ति पताका अद्यावधि फहर रही है। छत्रपति शाहूजी महाराज ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा नियुक्त किया जो 1720 तक पदासीन रहे। नाना फड़नवीस के दादा बालाजी महादजी भानु पेशवा के मित्र और मराठा साम्राज्य सेवा में कार्यरत थे। मुगलों द्वारा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हत्या की रची गई साज़िश का पर्दाफाश कर पेशवा की प्राण रक्षा करने पर नाना फड़नवीस के दादा को फडनवीस की उपाधि प्रदान की गई थी, जो आगे चलकर उनके वंश की पहचान बन गई। 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम पेशवा रहे, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारे और मराठा साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया। 1740 से 1761 तक बालाजी बाजीराव पेशवा का कार्यकाल रहा, जिनके सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। नाना फड़नवीस इन्हीं सदाशिवराव भाऊ के सचिव थे। पेशवा बालाजी बाजीराव के तीन पुत्र थे विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। वर्ष 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमदशाह अब्दाली और पेशवा के बीच हुआ। इस भयंकर युद्ध में मराठों की करारी हार हुई, शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई और आर्थिक स्थिति बदतर हो गई। युद्ध में राजकुमार विश्वासराव, सेनापति सदाशिवराव भाऊ सहित हजारों मराठा वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। नाना फड़नवीस सहित सीमित संख्या में मराठा नायक ही शेष बचे थे। आगे युद्ध की हार और पुत्र वियोग में पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक मंदिर में शोकावस्था में प्राण त्याग दिए। तब 1761 में बालाजी के 17 वर्षीय द्वितीय पुत्र माधवराव पेशवा पद पर आरूढ़ हुए।

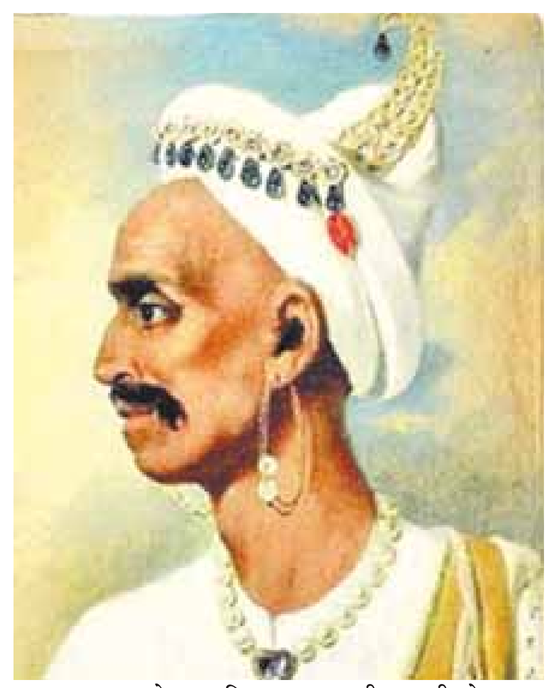

नाना फड़नवीस के परामर्श से पेशवा माधवराव मराठा साम्राज्य की गिरती साख को न केवल संभाल पाये बल्कि राज-काज को सुव्यवस्थित कर राज्य की बदहाली को दूर कर राजकोष को समृद्ध किया। इसी दौरान नाना फड़नवीस के नेतृत्व में निजाम को पराजित कर एक बड़ा क्षेत्र मराठा राज्य में मिला लिया। फड़नवीस की राह फूलों भरी नहीं, बल्कि कंटकमय थी। पेशवा माधवराव का सगा चाचा रघुनाथ राव राघोबा स्वयं पेशवा बनने की इच्छा पाले हुए था, और कुचक्र रच रहा था। किंतु नाना फड़नवीस की बुद्धिमत्ता, राजनीतिक समझ और प्रशासन पर सख्त पकड़ के चलते विरोधी सफल नहीं हो पा रहे थे। नाना ने अपनी मेधा से एक बहुत चतुर गुप्तचर विभाग स्थापित किया था, जो राज्य के किसी भी कोने में पेशवा के विरुद्ध रची जा रही दुरभिसंधि की सूचना नाना फड़नवीस को यथाशीघ्र पहुंचा देता था। मराठा राज्य विकास के पथ पर बढ़ रहा था पर नियति ने खेल खेला, पेशवा माधवराव का 1772 में निधन हो गया। छोटे भाई नारायणराव अब पेशवा बने, किंतु इनमें न राजकाज की पर्याप्त समझ थी और न ही राजनीतिक परिपक्वता। रघुनाथराव की पेशवा बनने की स्वप्न-बेल अब पुष्पित हो फलित होने को थी। अगस्त 1773 में अंगरक्षकों ने ही महल के अंदर नारायणराव की हत्या कर दी, और अंततः महत्वाकांक्षी रघुनाथराव पेशवा की गद्दी पर बैठा गया। नाना फड़नवीस के लिए यह असहनीय था।

उन्होंने सिंधिया, होल्कर, गायकवाड़, भोसले मराठा शक्ति का संघ बनाया और तुकोजीराव होल्कर, महादजी सिंधिया, हरिपंत फड़के, फलंटकर, भगवान राव प्रतिनिधि, सखारामबापू बोकिल, त्रिम्बकराम पेठे, सरदारजी रस्ते, बाबूजी नायक, मोलोजी घोरपड़े और मोरोबा फड़नीस आदि मंत्रियों की बाराभाई परिषद की रचना की। परिषद के साथ मिलकर रघुनाथराव को पदच्युत कर नारायणराव के 40 दिन के शिशु सवाई माधवराव को पेशवा पद पर आसीन करा स्वयं मुख्यमंत्री बन मराठा राज्य संभाल लिया। पर रघुनाथराव भाग कर ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगने चला गया और सूरत की संधि पर हस्ताक्षर कर कुछ महत्वपूर्ण मराठा क्षेत्र अंग्रजों को सौंप दिए, अंग्रेजों ने उसकी सैन्य मदद की। तभी इस संधि की काट के लिए कूटनीति से काम ले नाना फड़नवीस ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता परिषद के साथ पुरंदर की संधि कर ली, कंपनी रघुनाथ राव को पेंशन देने पर सहमत हुई। आगे अंग्रेजों से खतरा भांपते हुए 1777 में फड़नवीस ने पश्चिमी तट पर फ्रांसीसी सेना को बंदरगाह प्रदान किया। फलतः अंग्रेजों से मराठाओं का युद्ध हुआ। मराठे जीते और कंपनी द्वारा 1773 से जीते गये सभी क्षेत्र वापस ले लिए। आगे 1783 में पुनः अंग्रेजों को पराजित कर ग्वालियर के निकट सालबाई स्थान पर संधिपत्र पर हस्ताक्षर हुए। कंपनी ने रघुनाथ राव का समर्थन छोड़ दिया और मराठों की प्रभुता स्वीकार कर ली।

नाना फड़नवीस राज-काज में सख्त नियंत्रण रखते थे और मराठा साम्राज्य के गौरव के लिए पल-पल समर्पित। उनकी सूझ-बूझ और नेतृत्व से मराठा साम्राज्य की सीमाएं कृष्ण पक्ष के चंद्र की भांति बढ़ रही थीं। मराठा शक्ति फल-फूल रही थी, लोकजीवन आनंदमय था। दुर्योग से, 1796 में पेशवा सवाई माधवराव ने आत्महत्या कर ली और रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, जो नाना फड़नवीस को पसंद नहीं करता था। उसमें प्रशासनिक क्षमता न थी, फलतः मराठा साम्राज्य पतन की राह पर चल पड़ा। मराठा साम्राज्य की दुर्दशा से दुखी नाना फड़नवीस 13 मार्च, 1800 को स्वर्ग सिधार गये। पर अपने पीछे छोड़ गये निःस्वार्थ राजभक्ति, प्रजाहित, कूटनीतिक चातुर्य और बुद्धिमत्ता के वे चमकदार अध्याय, जिन्हें पढ़कर भावी पीढ़ी उन्हें नमन करती रहेगी।

कल्पना और अनुभव

मेघा राठी

लेखक साहित्यकार हैं।

जीवन की दो दिशाएँ, एक ही मंज़िल

कल्पना में कोई सीमा नहीं होती। वहाँ न परिस्थितियों का बंधन है, न असफलताओं का डर। एकांत में बैठकर रचा गया स्वप्न ही भविष्य की रूपरेखा बनता है। वैज्ञानिकों की खोजें, कवियों की रचनाएँ, कलाकारों की कृतियाँ, इन सबकी शुरुआत किसी शांत क्षण में ही हुई होगी। जब व्यक्ति दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर उतरता है, तब वह संभावनाओं के नए द्वार खोलता है। कल्पना हमें जीना सिखाती है क्योंकि वही हमें उद्देश्य देती है। यदि जीवन में कोई सपना न हो तो दिन केवल दिन रह जाते हैं उनमें कोई अर्थ नहीं बचता। कल्पना हमारे भीतर उत्साह जगाती है। वह कहती है 'तुम इससे बेहतर कर सकते हो।' यही प्रेरणा हमें संघर्ष करने की शक्ति देती है।

कल्पना का जन्म एकांत में और अनुभवों का भीड़ में होता है... कल्पना से जीना सीखते हैं और अनुभव से सहना सीखते हैं...' यह पंक्ति जीवन के दो गहरे आयामों को सरल शब्दों में सामने रख देती है। मनुष्य का अस्तित्व केवल बाहरी घटनाओं से निर्मित नहीं होता न ही वह केवल भीतर के स्वप्नों का परिणाम है। उसके जीवन की पूर्णता इन दोनों के संतुलन में छिपी है–एकांत की कल्पना और भीड़ के अनुभव में।

एकांत : जहाँ कल्पना आकार लेती है–

एकांत केवल अकेले बैठ जाना नहीं है यह स्वयं से मिलने का अवसर है। जब बाहरी शोर थम जाता है तब भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। वही आवाज़ कल्पना को जन्म देती है। एकांत में बैठा व्यक्ति अपने मन के आकाश में उड़ान भरता है। वह सोचता है मैं क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ।

कल्पना में कोई सीमा नहीं होती। वहाँ न परिस्थितियों का बंधन है, न असफलताओं का डर। एकांत में बैठकर रचा गया स्वप्न ही भविष्य की रूपरेखा बनता है। वैज्ञानिकों की खोजें, कवियों की रचनाएँ, कलाकारों की कृतियाँ, इन सबकी शुरुआत किसी शांत क्षण में ही हुई होगी। जब व्यक्ति दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर उतरता है, तब वह संभावनाओं के नए द्वार खोलता है।

कल्पना हमें जीना सिखाती है क्योंकि वही हमें उद्देश्य देती है। यदि जीवन में कोई सपना न हो तो दिन केवल दिन रह जाते हैं उनमें कोई अर्थ नहीं बचता। कल्पना हमारे भीतर उत्साह जगाती है। वह कहती है 'तुम इससे बेहतर कर सकते हो।' यही प्रेरणा हमें संघर्ष करने की शक्ति देती है।

भीड़ : जहाँ अनुभव परिपक्व होते हैं- यदि एकांत हमें सपने देता है तो भीड़ हमें उनकी परीक्षा का अवसर देती है। समाज में रहकर ही हम जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होते हैं। परिवार, मित्र, कार्यस्थल, रिश्ते...इन सबके बीच हमें तरह-तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहीं से अनुभव जन्म लेते हैं।

भीड़ में चलना आसान नहीं। यहाँ मतभेद हैं, प्रतिस्पर्धा है, अपेक्षाएँ हैं। कभी प्रशंसा मिलती है, कभी आलोचना। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। इन सबके बीच जो हम सीखते हैं, वही अनुभव है।

अनुभव हमें सहना सिखाते हैं। जीवन में हर चीज़ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कई बार हमें समझौता करना पड़ता है, कई बार अपने अहं को पीछे रखना पड़ता है। अनुभव बताते हैं कि हर हार अंत नहीं होती और हर जीत स्थायी नहीं होती। वे हमें धैर्य, संयम और विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं।

कल्पना और अनुभव का संबंध–

कल्पना और अनुभव विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। केवल कल्पना में जीने वाला व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो सकता है। वह सपने तो देखेगा पर उन्हें पूरा करने का साहस और कौशल उसके पास नहीं होगा। दूसरी ओर, केवल अनुभवों में उलझा व्यक्ति कठोर हो सकता है। यदि उसके जीवन में कोई सपना न हो, तो वह केवल परिस्थितियों का दास बनकर रह जाएगा।

जीवन का सौंदर्य तब है जब कल्पना और अनुभव साथ चलें। एकांत में जो सपना जन्म लेता है, उसे भीड़ में जाकर अनुभवों की अग्नि से गुजरना होता है। वही सपना जब कठिनाइयों के बीच टिक जाता है, तो वास्तविकता बनता है।

सहना और जीना : दो अलग पर जुड़ी हुई प्रक्रियाएँ

'कल्पना से जीना सीखते हैं और अनुभव से सहना सीखते हैं '–यह वाक्य जीवन की गहराई को छूता है। जीना केवल सांस लेना नहीं है; जीना है उत्साह, आशा और आनंद के साथ आगे बढ़ना। यह शक्ति कल्पना से आती है। जब मन में कोई सुंदर भविष्य की तस्वीर होती है, तब वर्तमान की कठिनाइयाँ भी छोटी लगती हैं।

सहना एक अलग कला है। सहना का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है। जब जीवन हमें ठोकर देता है, तो अनुभव हमें संभालता है। वह कहता है , 'तुम पहले भी गिरे हो, फिर उठे हो।' यही सीख हमें टूटने से बचाती है।

आधुनिक जीवन में इन दोनों की भूमिका

आज का समय तेज़ गति का है। सोशल मीडिया की भीड़, प्रतियोगिता का दबाव, अपेक्षाओं का बोझ इन सबके बीच व्यक्ति का एकांत खोता जा रहा है। जब एकांत कम होता है, तो कल्पना भी सीमित हो जाती है। हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने सपने तय करने लगते हैं।

दूसरी ओर, अनुभव भी सतही हो गए हैं। हम घटनाओं को महसूस करने से पहले ही आगे बढ़ जाते हैं। न ठहराव है, न चिंतन। परिणामस्वरूप न तो कल्पना गहराई पाती है, न अनुभव परिपक्वता। ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम अपने लिए थोड़ा एकांत बचाएँ कुछ क्षण जहाँ हम केवल स्वयं के साथ हों। वहीं से नए विचार जन्म लेंगे। साथ ही, हमें अपने अनुभवों को समझने के लिए भी ठहरना होगा। हर घटना हमें कुछ सिखाती है, यदि हम सीखने के लिए तैयार हों।

संतुलन की कला–

जीवन की परिपक्वता इसी में है कि हम एकांत और भीड़, कल्पना और अनुभव, जीने और सहने के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। जब हम अकेले हों, तो सपने देखें; जब समाज में हों, तो उन सपनों को परखें। एकांत हमें दिशा देता है, अनुभव हमें दृढ़ता। एकांत हमें ऊँचाई दिखाता है, अनुभव हमें जमीन से जोड़े रखता है। यदि केवल ऊँचाई हो, तो गिरने का खतरा है; यदि केवल जमीन हो, तो उड़ान संभव नहीं।

मनुष्य का जीवन एक यात्रा है भीतर से बाहर की और बाहर से भीतर की। एकांत में जन्मी कल्पना हमें उड़ना सिखाती है, और भीड़ में मिले अनुभव हमें गिरकर संभलना सिखाते हैं। दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में दोनों के लिए स्थान रखें। जब थक जाएँ, तो एकांत में लौटकर अपने सपनों को नया रूप दें और जब सपनों को साकार करने का समय आए तो भीड़ में उतरकर अनुभवों से सीखें। यही जीवन की सच्ची साधना है कल्पना से जीना और अनुभव से सहना।

आदिवासी

उमंग सिंघार

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

आदिवासियों की पहचान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी

देश के कई राज्यों में आदिवासी समाज लंबे समय से अलग धर्म कोड की मांग करता रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है। लेकिन, इस मांग को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है। मध्य प्रदेश से ही 50 लाख आवेदन राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं, तो यह एक मजबूत संदेश होगा कि आदिवासी समाज अपनी पहचान के लिए एकजुट है। आदिवासी समाज अपनी अलग धार्मिक पहचान को मान्यता दिलाने की वाजिब मांग कर रहा है।

मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट पहचान, परंपराओं और संस्कृति के साथ सदियों से जीवन जीता आया है। उनकी प्रकृति-आधारित जीवनशैली, लोक आस्थाएं और सामाजिक व्यवस्था मुख्यधारा के धर्मों से अलग और विशिष्ट रही हैं। इसके बावजूद आज तक जनगणना और सरकारी अभिलेखों में आदिवासी समाज को उनकी वास्तविक पहचान नहीं मिल पाई। यही कारण है कि अब समय आ गया है जब आदिवासी समाज को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए एक अलग 'धर्म कोड' की व्यवस्था की जाए। यह केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि करोड़ों आदिवासियों के आत्मसम्मान, संस्कृति और अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है।

आदिवासी समुदाय की आस्था और जीवन पद्धति किसी एक संगठित धर्म की तरह नहीं है। उनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा है। जंगल, पहाड़, नदियां और धरती उनके लिए केवल संसाधन नहीं बल्कि पूजनीय तत्व हैं। आदिवासी समाज में प्रकृति पूजा, सामुदायिक परंपराएं और लोक देवताओं की मान्यता रही है। ये परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन, जब जनगणना में उन्हें किसी अन्य धर्म के अंतर्गत गिना जाता है, तो उनकी यह अलग पहचान धीरे-धीरे धुंधली पड़ने लगती है। यही कारण है कि अब आदिवासी समाज अपनी अलग धार्मिक पहचान को मान्यता दिलाने की मांग कर रहा है।

यह मांग अचानक नहीं जन्मी। देश के कई राज्यों में आदिवासी समाज लंबे समय से अलग धर्म कोड की मांग करता रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है। आज जब हम आदिवासी अधिकारों और उनके सम्मान की बात करते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि उनकी पहचान को भी संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से स्वीकार किया जाए। अगर आदिवासी समाज को लगातार अन्य धर्मों की श्रेणी में रखा जाता रहेगा, तो आने वाले समय में उनकी पारंपरिक आस्थाएं और सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ सकती है। यह केवल सांस्कृतिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह उनके अस्तित्व पर भी असर डाल सकता है।

आदिवासी समाज की इस मांग को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है। इसलिए आदिवासी समाज से अपील की गई है, कि वे राष्ट्रपति को बड़े पैमाने पर पत्र भेजें। यदि केवल मध्य प्रदेश से ही 50 लाख आवेदन राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं, तो यह एक मजबूत संदेश होगा कि आदिवासी समाज अपनी पहचान के लिए एकजुट है। यह कदम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का माध्यम है। जब करोड़ों लोगों की आवाज एक साथ उठेगी, तभी सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के बजाय इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री विश्वास सारंग ने इस मांग को लेकर आपत्ति जताई है और इसे अनावश्यक विवाद बताने की कोशिश की है। लेकिन, सवाल यह है कि अगर आदिवासी समाज अपनी पहचान की बात कर रहा है, तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। क्या अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने की मांग करना गलत है? इस तरह के विरोध से यह संदेश जाता है कि कुछ लोग आदिवासी समाज की वास्तविक चिंताओं को समझने के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जबकि, यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर आदिवासी अस्मिता से जुड़ा हुआ है।

भारत का संविधान विविधता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है। देश में अनेक धर्मों और परंपराओं को मान्यता दी गई है। ऐसे में आदिवासी समाज की अलग धार्मिक पहचान को स्वीकार करना भी उसी संवैधानिक भावना का हिस्सा है। यह किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए उठाई गई मांग है। जब तक आदिवासी समाज की पहचान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक उनकी संस्कृति को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा।

आज जरूरत इस बात की है कि आदिवासी समाज की आवाज को गंभीरता से सुना जाए। अलग धर्म कोड की मांग किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए उठाई गई है। अगर हम सच में आदिवासी समाज का सम्मान करना चाहते हैं, तो उनकी पहचान को स्वीकार करना ही होगा। यह कदम केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह करोड़ों आदिवासियों के आत्मसम्मान और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकता है।

डीसैलिनेशन प्लांटः समुद्र के पानी को पेयजल में बदलने का जतन

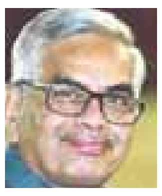

चर्चा में

ब्रजेश कानूनगो
लेखक स्तंभकार हैं।

जब ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका की जंग लगातार बढ़ती गई तो दोनों ही खेमों का निशाना तेल और मिसाइल से आगे बढ़कर पानी तक पहुंच गया। ऐसे में डीसैलिनेशन प्लांट (विलवणीकरण संयंत्र) यानी जल शुद्धिकरण संयंत्र को टार्गेट किया जाने लगा तो हमारा ध्यान इस बात की ओर गया कि विश्व के अनेक देशों में जहां शुद्ध पेयजल की कमी है वहां बड़े पैमाने पर समुद्र के खारे जल को परिष्कृत करने के लिए पीने के पानी में बदला जा रहा है।

समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाना (Desalination) आज के समय में जल संकट से निपटने का एक क्रांतिकारी तरीका बन गया है। दुनिया के कई देश अपनी पानी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी तकनीक से पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में दुनिया भर में हजारों डिसेलिनेशन प्लांट काम कर रहे हैं। कुछ प्रमुख देशों ने बड़े पैमाने पर यह तकनीक अपनाई है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जल शोधक देश है। यहाँ के पानी की लगभग 50% से अधिक आपूर्ति इसी माध्यम से होती है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई और अबू धाबी जैसे शहर लगभग पूरी तरह से शोधित समुद्री पानी पर निर्भर हैं। इजराइल अपनी उन्नत तकनीक के कारण इजराइल अपनी घरेलू पानी की जरूरत का करीब 75% हिस्सा समुद्र से प्राप्त करता है। कुवैत, कतर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका (विशेषकर कैलिफोर्निया) और भारत (चेन्नई और गुजरात में कुछ बड़े प्लांट) भी इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं।

एक खबर के अनुसार युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप के वॉटर प्लांट पर हमला करके उसके 30 गांवों को प्यासा कर दिया। जवाब में ईरान ने भी टार्गेट बदलते हुए बहरीन में वॉटर डिसेलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि ये प्लांट्स यहां के जनजीवन के लिए सर्वोच्च महत्व के संयंत्र हैं। इनके ऊपर हमला होना इस पूरे क्षेत्र के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर इन प्लांट्स पर आगे भी हमला जारी रहे या साइबर अटैक हो या पानी दूषित कर दिया जाए तो यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में मानव सुरक्षा का गंभीर संकट संभावित हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर इन प्लांट्स को नुकसान हुआ तो शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी तुरंत ठप हो सकती है।

बहरहाल, अब समझते हैं कि वाटर डीसैलिनेशन प्लांट कैसे काम करते हैं। दरअसल समुद्र के पानी से नमक अलग करने की मुख्य रूप से दो वैज्ञानिक विधियां सबसे अधिक प्रचलित हैं। जिनमें से पहली है रिवर्स ऑस्मोसिस (Reverse Osmosis - RO) जो सबसे आधुनिक और ऊर्जा-कुशल तकनीक है। इसमें समुद्र के पानी को बहुत उच्च दबाव (High Pressure) पर एक 'अर्ध-पारगम्य झिल्ली' (Semi-permeable Membrane) से गुजारा जाता है। यह झिल्ली इतनी सूक्ष्म होती है कि इसमें से पानी के अणु तो निकल जाते हैं, लेकिन नमक और अन्य अशुद्धियाँ पीछे रह जाती हैं।

डिसेलिनेशन की दूसरी विधि है थर्मल डिसेलिनेशन (Thermal Desalination) इसमें 'वाष्पीकरण' (Evaporation) के सिद्धांत पर काम होता है। पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है, जिससे नमक नीचे बैठ जाता है। फिर उस भाप को ठंडा (Condensation) करके शुद्ध पानी के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। मध्य पूर्व के देशों में, जहाँ ऊर्जा सस्ती है, वहां इस तकनीक का काफी उपयोग होता है।

डीसैलिनेशन प्रक्रिया केवल नमक हटाने तक सीमित नहीं है, इसमें कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। प्री-ट्रीटमेंट (Pre-treatment) के तहत समुद्र से लिए गए पानी से पहले कचरा, रेत और शैवाल (Algae) को छाना जाता है ताकि मुख्य झिल्ली (Membrane) खराब न हो। फिर होता है डिसेलिनेशन (Desalination) जिसके अंतर्गत RO या थर्मल तकनीक के जरिए नमक को अलग किया जाता है। बाद में पोस्ट-ट्रीटमेंट (Post-treatment) में शुद्ध किए गए पानी का स्वाद बेहतर करने और उसे स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए इसमें जरूरी खनिज (Minerals) जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाए जाते हैं। तत्पश्चात अपशिष्ट निपटान (Brine Disposal) के दौरान बचा हुआ अत्यधिक खारा पानी (Brine) वापस समुद्र में सावधानीपूर्वक विसर्जित किया जाता है।

एक भारतीय व्यक्ति होने के नाते आम जिज्ञासा सहज है कि अपने देश में समुद्र के पानी से पेय जल बनाने की दिशा में क्या कुछ कार्य किया गया है। भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु और गुजरात में सबसे बड़े और प्रभावी प्लांट स्थित हैं। यहाँ के पानी का उपयोग और वितरण (Usage and Distribution) मुख्य रूप से दो श्रेणियों में किया जाता है। घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। चेन्नई में CMWSSB(Metrowatrer) पाइपलाइनों के माध्यम से इस पानी को घरों तक पहुँचाता है। दक्षिण और उत्तर चेन्नई के लगभग 30-40 लाख लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इसी पर निर्भर हैं। भविष्य में 'पेरूर प्लांट' के पूरा होने पर यह संख्या और बढ़ जाएगी। लक्षद्वीप में छोटे LTTD (Low Temperature Thermal Desalination) प्लांट लगे हैं, जो द्वीपों पर रहने वाले समुदायों को मीठा पानी प्रदान करते हैं।

औद्योगिक उपयोग (Industrial Water) के अंतर्गत गुजरात के दहेज (Dahej) और जामनगर जैसे क्षेत्रों में पानी का उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। गुजरात औद्योगिक विकास निगम (GIDC) दहेज में स्थित पेट्रोलियम और केमिकल कंपनियों को पानी की आपूर्ति करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि उद्योगों को समुद्र का पानी देने से खेती और पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले ताजे पानी यानि नदियों के पानी की बचत होती है।

डीसैलिनेशन प्रक्रिया को भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) ने भी विकसित किया है। यह तकनीक समुद्र की सतह और गहराई के पानी के तापमान के अंतर का उपयोग करती है। यह लक्षद्वीप के लिए वरदान साबित हुई है।

भारत जैसे देश के लिए डीसैलिनेशन के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं इस प्रक्रिया में मसलन इसकी लागत बहुत अधिक होती है, पाइपलाइन से आने वाले साधारण पानी की तुलना में डिसेलिनेशन का पानी 3 से 4 गुना महंगा हो जाता है।

इसके अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से समुद्र से पानी निकालने के बाद बचा हुआ ब्राइन (अत्यधिक खारा घोल) वापस समुद्र में डालने से समुद्री जीवों को नुकसान पहुँच सकता है, जिसे कम करने के लिए भारत में 'मल्टी-डिस्कस' तकनीक पर काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र (मुंबई के मनोरी में प्रस्तावित) और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी अब इस दिशा में बड़े कदम उठा रहे हैं।

विख्यात फोर्सिथ रिसोर्ट से अनाधिकृत वन्यप्राणी अवयव जप्त

हीरालाल गोलानी सोहागपुर । सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई एक ओर जहां देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। जिससे देश,विदेश के पर्यटकों की आमद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सीज़न के समय यहां के समस्त रिसोर्ट फुल नो रूम हो जाते हैं।ऐसे में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के वन परिक्षेत्र बागड़ा बफर अंतर्गत मढई में स्थित विख्यात फोर्सिथ रिसोर्ट की जांच की गई जिसमें वन्यप्राणी चीतल के एन्टलर (सींग) 04 नग, सेही के कांटे 04 नग एवं सर्प की कांचली 02 नग अनाधिकृत रूप से बिना किसी स्वीकृति के डिस्प्ले में रखी हुई पाई गई। जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। सहायक संचालक सोहागपुर आशीष खोब्रागड़े के निर्देशन में उक्त वन्यप्राणियों के अवयवों को जप्त कर आपराधिक प्रकरण तैयार कर विस्तृत जांच की जा रही है। बड़ा सवाल आखिर उक्त वन प्राणियों के अव्यय कहां से प्राप्त किए गए। क्या उनका शिकार करके प्राप्त हुए हैं। फिर बेखोफ तरीके से पर्यटकों को लुभाने के लिए डिस्प्ले में रखे गए थे। आखिर उक्त बातें रिसोर्ट के बाहर कैसे नहीं आई होगी? कहीं न कहीं दाल में कुछ काला जरूर है?

वन्य प्राणियों के अव्यय जप्त

मढ़ई स्थित फोर्सिथ रिसोर्ट विख्यात है , उच्च स्तरीय जांच हो

सोहागपुर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढई बांग्ला रेंज में स्थित विख्यात फोर्सिथ रिसोर्ट यह एक प्रीमियम 4 स्टार रिसोर्ट की श्रेणी में आता है। उक्त विख्यात फोर्सिथ रिसोर्ट करीबन 4 4एकड़ में फैला हुआ है। फोर्सिथ लॉज (फॉरसिथ लॉज), जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास स्थित है, 44 एकड़ के विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इस 44 एकड़ के क्षेत्र में से, केवल 10% से कम यानी लगभग 4 एकड़ में ही निर्माण (कॉटेज और मुख्य भवन) किया गया है,जिसमें मिट्टी से बने आलीशान 12 काटेज हैं। जिसमें मचान काटेज, डोडिया काटेज ,निजी बालकनी के विकल्प हैं।

जिसमें एक दिन का किराया 15 हजार से 25 हजार रूपये है। लेकिन सीज़न के समय इसका किराया और अधिक बढ़ जाता है। बताया जाता है कि इस रिसोर्ट में विदेशी सैलानियों की भी आवक होती रहती है। पता चला है कि करीबन 40 एकड़ बाकी हिस्सा प्राकृतिक जंगल है।ऐसे में विख्यात फोर्सिथ रिसोर्ट में वन्य प्राणियों के अव्यय मिलना संदिग्धता एवं संलिप्तता को दर्शाता है। इस मामले में उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। ताकि वास्तविकता का पता चला सके।

धार जिले में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर आपदा प्रबंधन की तैयारी परखी, गेल इंडिया लिमिटेड ने किया ऑफसाइट मॉक ड्रिल का आयोजन

जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस और विभिन्न एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी, गैस रिसाव और आग की आपात स्थिति से निपटने का किया अभ्यास

धार। गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसके पास प्राकृतिक गैस के गैस प्रसंस्करण संयंत्रों के साथ-साथ तक़रीबन 20,000 किलोमीटर क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। गेल, खेड़ा कम्प्रेसर स्टेशन, चिकली जिला उज्जैन विभिन्न जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, राजगढ़, आगर और रतलाम में मध्य प्रदेश में लगभग 778 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के प्रचालन एवं प्रबंधन की देखरेख कर रहा है ।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क पर संभावित आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से गेल (इंडिया) लिमिटेड खेड़ा कम्प्रेसर स्टेशन ने जिला प्रशासन-धार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और पारस्परिक सहायता भागीदारों के सहयोग से 12 मार्च को मॉक ड्रिल का आयोजन किया।

ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य गेल (इंडिया) लिमिटेड, खेड़ा और जिला प्रशासन की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से किसी भी आपात स्थिति में भाग लेने के लिए संसाधनों की प्रभावकारिता, कौशल और पर्याप्तता का मूल्यांकन और जांच करना और आपातकालीन तैयारी प्रणालियों में और सुधार करना था।

आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए 36' एचवीजे (हजीरा विजयपुर जगदीशपुर) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के सीएच (chainage) नंबर 377.000 किलोमीटर पर, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं पीएचसी परिसर के समीप, ग्राम मूल्थान, तहसील बदनावर, जिला धार मे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर आग/विस्फोट के बाद विपुल गैस रिसाव का एक नकली परिदृश्य बनाया गया था।

साइट पर बनाया गया दृश्य...

जेसीबी ऑपरेटर ने जमीन की खुदाई करते समय अनजाने में भूमिगत 36 'इंच एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को छतिग्रस्त (पंक्चर) कर दिया जिससे भारी गैस रिसाव शुरू हो गया और उसके बाद आग और विस्फोट हुआ।

आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने गैस रिसाव और उसकी रोकथाम, सड़क यातायात नियंत्रण, बचाव और हताहतों को स्वास्थ्य देखभाल केंद्र/अस्पताल में स्थानांतरित करने, आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को निकालने और राहत शिविरों में स्थानांतरित करने आदि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया, ड्रिल के दौरान प्रभावी ढंग से समन्वय किया गया।

गेल, खेड़ा कंप्रेसर स्टेशन- चिकली, राज्य जिला प्रशासन धार, एस.डी.एम- बदनावर द्वारा निर्देशित टीम, अरविंद सिंह तोमर -एसडीओपी- बदनावर, सुरेश नागर, तहसीलदार- बदनावर, एसडीआरएफ टीम (डीसी होमगार्ड), अग्निशमन सेवा- बदनावर तहसील, जिला आपदा प्रबंधन केंद्र, पुलिस अधिकारी, जिला चिकित्सा सेवाएं, और पारस्परिक सहायता भागीदार (Mutual Aid Partners) यानी गेल गैस, अवंतिका गैस, बीपीसीएल, मेघा गैस, आईएचबी-धार और आईओसीएल-बीपी, घटिया के सभी संबंधित विभागों ने मॉक ड्रिल अभ्यास को अत्यधिक सफल बनाने के लिए अपनी परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार सक्रिय रूप से भाग लिया। आपातकाल से निपटने के लिए गेल-खेड़ा, नगर परिषद - बदनावर तहसील, बीपीसीएल (ERV) और आईएचबी धार से फायर टेंडर सेवा में लगाए गए थे।

अविनाश बाउस्कर, महाप्रबंधक और प्रभारी अधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड-खेड़ा, उज्जैन ने एसडीओपी- बदनावर, तहसीलदार- बदनावर, पुलिस थाना प्रभारी-बदनावर और प्लाटून कमांडेंट (एसडीआरएफ-धार) की उपस्थिति और पर्यवेक्षण में ड्रिल कार्यवाही को नियंत्रित किया। इस मॉक अभ्यास का कुशलतापूर्वक नियंत्रण और प्रबंधन अविनाश बाउस्कर, महाप्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, खेड़ा, उज्जैन के नेतृत्व में टीम द्वारा किया गया ।

ड्रिल के समापन के बाद, साइट पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी कमियों और कमियों के रूप में सकारात्मक निष्कर्षों पर आगे सुधार के लिए प्रमुख हितधारकों द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

एक्सीलेंस चयन परीक्षा, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा में छाए सदर स्कूल के विद्यार्थी

जिले भर से 3989 विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा, 11 मेरिट लिस्ट और 5 का स्कॉलरशिप के लिए चयन

बैतूल। शासकीय हाई स्कूल सदर बैतूल की छात्राएं एक्सीलेंस स्कूल और राष्ट्रीय मीन्स कम मैरिड परीक्षा में छाएं रहे। इस स्कूल के 16 विद्यार्थियों ने ना केवल सफलता हासिल की, बल्कि मेरिट सूची में स्थान हासिल किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से स्कूल स्टाफ बेहद खुश है। उनका कहना है कि यह सफलता विद्यार्थियों के साथ स्कूल की भी है। इस परीक्षा से बच्चों और अच्छी शिक्षा हासिल होगी और कई बच्चों को हजारों रुपए की स्कारशिप हासिल हो सकेगी। स्कूल की प्राचार्य इंद्रावती लिल्होरे ने बताया कि जिले भर से 3989 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। उत्कृष्ट विद्यालय चयन प्रवेश परीक्षा 2026 में स्कूल के 29 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान बनाया है। इसमें दुर्गा उइके 53वें, आदिका खड़ीपुरे 55वें ,स्नेहा पदाम 67वें स्थान पर संतोषी राठौर 14वे , संजना पदांम 5वें, मुस्कान मर्सकोले 23वें, पूनम उईके 25वें, हिमांशी कुमरे 26वें, मयूरी पदांम 52वे, आंचल कुमरे 77वें , प्रतिमा परते 93वें स्थान स्थान हासिल कर उत्कृष्ट चयन परीक्षा में चयनित हुई है। इसी तरह राष्ट्रीय मींस का मेरिट चयन परीक्षा में 26 में से 5 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल कर मेरिट में स्थान बनाया। इसमें संतोषी राठौर 26 वें स्थान पर स्नेहा पदाम 88वें, अद्विका खादीपुरे 170 वें, हिमांशी कुमरे 173 वें और दुर्गा उइके 192वें स्थान पर आकर स्कूल को गौरान्वित किया है। प्राचार्य इंद्रावती लिल्होरे ने स्कूल के सभी शिक्षकों के अथक प्रयास की सराहना करते हुए छात्राओं को अच्छी शिक्षा हासिल कर परिवार का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

लीजिए साहब अब नगर पंचायत रात्रि के समय, अवकाश के दिन में निर्माण कार्य में लगी है?

सोहागपुर। लीजिए साहब प्रदेश सरकार की अनूठी सोहागपुर नगर पंचायत परिषद रात्रि के समय तथा अवकाश के दिन में भी निर्माण कार्य में लगी हुई है। उक्त आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बैलवशी ने लगाकर सोशल मीडिया के ग्रुप्स में डाला है। श्री बैलवशी ने कहा है कि नगर परिषद सोहागपुर में कायाकल्प योजना में सीमेंट रोड का निर्माण ठेकेदारों द्वारा विभिन्न वार्डो में किया जा रहा है।

सीमेंट रोड निर्माण में ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जारी है। क्या इसमें जनप्रतिनिधियों/सीएमओ और उप यंत्री जी की मौन स्वीकृति है? यह कि ठेकेदार द्वारा अधिकतर निर्माण अवकाश के दिन अथवा रात्रि के समय किए जा रहे है। आपने आरोप लगाया है कि क्या इस पर सी एम ओ या उपयंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं है । ऐसा प्रतीत हो रहा है।अवकाश के दिन या रात्रि के समय ठेकेदार मनमाने तरीके से घटिया निर्माण कर रहे है। और उपयंत्री जी मेजरमेंट कर रहे हैं ।सी एम ओ और अध्यक्ष महोदया जी ठेकेदार के भुगतान कर रही है।ठेकेदार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण तिलक वार्ड में निर्मित रोड पर देख सकते है श्री बैलवशी कहते हैं कि इस रोड का निर्माण रविवार को प्रारंभ किया गया और सोमवार की सुबह होने से पहले ही निर्माण पूर्ण हो गया। इस रोड के निर्माण को महज 15 दिन ही हुए है। और रोड पर गुट्टी निकलने लगी है ज्वाइंट टूटने लगे है।

मैं सीएमओ और उप यंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड के निर्माण में आपकी मौन स्वीकृति थी कि कोई मैनिटिरिंग नहीं करेगा ।आप संडे को रोड बना दे। और सोमवार के पहले पूरी कर दे।

नगर वासियों से निवेदन है कि क्या कल्प योजना में नगर में घटिया निर्माण चल रहे है शासन और नगर वासियों के टैक्स के पैसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे है। सी एम ओ और उप यंत्री महोदय नगर में हो रहे घटिया निर्माण पर ठेकेदार पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?और बिलों का भुगतान कैसे किया जा रहा है?

तमिलनाडु में बंधुआ बनाए गए 20 श्रमिकों का बैतूल प्रशासन ने कराया सफल रेस्क्यू

बैतूल। तमिलनाडु के इरोड जिले में बंधुआ बनाकर रखे गए बैतूल जिले के 20 श्रमिकों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिला प्रशासन तथा वनवासी कल्याण आश्रम के त्वरित एवं समन्वित प्रयासों से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सभी श्रमिकों के बैतूल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष महेश्वर भलावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, एसडीएम अभिजीत सिंह, जिला श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत, थाना प्रभारी नीरज पाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। स्टेशन पर सभी श्रमिकों की पहचान सुनिश्चित की गई। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने श्रमिकों से आत्मीय चर्चा करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा उनके सुरक्षित गृह पहुंचने की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए राजस्व, पुलिस और श्रम विभाग निरंतर उनके संपर्क में रहेंगे। साथ ही श्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया कि श्रमिकों से संपर्क बनाए रखते हुए आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं। रेलवे स्टेशन से सभी श्रमिकों को उनके गृह ग्राम तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई तथा भोजन की भी व्यवस्था की गई। सुरक्षित वापसी पर श्रमिकों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। जिला श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत ने बताया कि उक्त श्रमिक काम करने के लिए तमिलनाडु के इरोड जिले गए थे, जहां होली पर्व पर अवकाश मांगने पर उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और बंधुआ बनाकर कार्य कराया जा रहा था।

संक्षिप्त समाचार

शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को दिया कैरियर मार्गदर्शन

बैतूल (निप्र)। शासकीय कन्या महाविद्यालय बैतूल में मंगलवार को रोजगार कार्यालय के द्वारा छात्राओं को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस दौरान शासकीय, अशासकीय तथा उद्योग धंधों में किस प्रकार अपना करियर बना सकते हैं का मार्गदर्शन आर्ट्स कॉमर्स होम साइंस की छात्राओं को दिया गया। मनोवैज्ञानिक काउंसलर श्री अमीनुद्दीन खान ने रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार दिए जाने की जानकारी दी। काउंसलर श्रीमती साधना धुर्वे द्वारा अपने-अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार किस तरह जॉब की तैयारी की जाए बताया गया। इसके अलावा छात्राओं को कोचिंग संस्थानों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई सदर में 11 मार्च को आयोजित होने वाले रोजगार मेले के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों में जॉब की जानकारी दी गई। विष्णु धुर्वे द्वारा रोजगार कार्यालय में पंजीयन की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विद्या चौधरी ने छात्राओं को जागरूक रहने की सलाह दी। महाविद्यालय परिवार डॉ.साधना डेहरिया, प्रो माधुरी पल्ले, प्रो.नव सिखा श्रीवास, डॉ.प्रीति भादे, डॉ.सीमा बेलवंशी, आरती दीक्षित, पंकज पवार सहित महाविद्यालय की 70 छात्राएं उपस्थित थी।

नरवाई नही जलाने के लिए जागरूक एवं उन्नतशील किसानों के माध्यम से किया जा रहा अन्य किसानों को प्रेरित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को नरवाई प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अनेक ग्रामों के जागरूक और उन्नतशील किसानों से संपर्क किया जा रहा है और उन किसानों के सहयोग से अन्य किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण जिले के ग्राम आमाझिर में देखने को मिला जहां ग्राम के उन्नतिशील किसान श्री सचिन वर्मा ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने गांव के किसानों को नरवाई जलाने के नुकसानों से अवगत कराया और इसके वैकल्पिक तरीकों के बारे में जानकारी दी। ग्राम के सभी किसानों ने अपनी साथी किसान श्री सचिन वर्मा के सुझावों सहमति दी और नरवाई नही जलाने का संकल्प लिया। इस दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री बीएस देवड़ा सर एवं क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री दीपिका नागर उपस्थित थे। इसके अलावा इस संबंध में कृषि विभाग के अमले द्वारा गांव-गांव में लाउडस्पीकर के माध्यम से किसानों को समझाइश दी जा रही है कि वे फसल अवशेष (नरवाई) को जलाने के बजाय वैज्ञानिक तरीकों से उसका प्रबंधन करें। साथ ही किसानों को नरवाई प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव हो और कृषि उत्पादन भी अधिक हो। कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की जा रही है कि वे नरवाई न जलाएं और बताए गए वैकल्पिक उपायों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत जिले की 34 बालिकाओं को लगाई गई एचपीवी की वैक्सीन

सीहोर (निप्र)। शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉ सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि सीहोर जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में भी एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को एचपीवी की वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 09 मार्च को जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जिले की 34 बालिकाओं को एचपीवी की वैक्सीन लगाई गई। सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे जानलेवा कैंसर है। इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह राष्ट्रव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान आगामी तीन माह तक पूरे देश में संचालित किया जाएगा।

रीपर कम बाइंडर एवं स्ट्रॉ रीपर का कृषकों के बीच जीवंत प्रदर्शन

बैतूल (निप्र)। गेहूं कटाई के बाद हर वर्ष सामने आने वाली नरवाई जलाने की समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस वर्ष विशेष तैयारी की गई है। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों के बीच रीपर कम बाइंडर एवं स्ट्रॉ रीपर यंत्र का जीवंत प्रदर्शन तथा नरवाई प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैतूल विकासखंड के ग्राम रौंदा के प्रगतिशील किसान श्री संजय कुमार साहू ने आधुनिक कृषि यंत्रीकरण अपनाकर न केवल अपनी खेती की लागत कम की, बल्कि फसल अवशेष प्रबंधन में भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसान द्वारा रीपर कम बाइंडर से गेहूं की कटाई की गई, जिसका प्रदर्शन अन्य किसानों के सामने किया गया। कार्यशाला में सहायक कृषि यंत्री डॉ. प्रमोद कुमार मीना ने यंत्र की कार्यप्रणाली तथा अनुदान प्रक्रिया की जानकारी किसानों को दी। उन्होंने बताया कि इस यंत्र से कटाई के बाद खेत में गेहूं की नरवाई केवल 4-5 इंच तक ही बचती है, जिससे उसे जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और अगली फसल के लिए खेत जल्दी तैयार हो जाता है। इसी क्रम में ग्राम हिवड़खेड़ी में भी नरवाई प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें स्ट्रॉ रीपर यंत्र का फील्ड प्रदर्शन किया गया। कम्बाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के बाद स्ट्रॉ रीपर के माध्यम से नरवाई को भूसे में परिवर्तित कर किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉ रीपर से तैयार भूसा बाजार में लगभग 2000 रुपये प्रति ट्रॉली तक बिक जाता है।

फार्मर रजिस्ट्री सहित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाए : कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी

भगवान बिरसा मुंडा, संत रविदास एवं टंट्या मामा योजना में शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाए कमिश्नर ने विभिन्न विभागो की योजनाओ, लक्ष्यो की प्रगति की अदयतन स्थिति की समीक्षा की

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों के पंजीयन होने के पश्चात भी प्रकरणों के निराकरण में तेजी न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह फार्मर रजिस्ट्री सहित राजस्व के अन्य प्रकरण जैसे सीमांकन, बटवारा, अभिलेख दूरूस्ती करण, रास्ते का विवाद, एग्री स्टेक आदि के प्रकरण का तेज गति से निराकरण करें। साथ ही निर्देश दिए की साइबर तहसील के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण 10 दिन की समय सीमा में अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर साइबर तहसील में प्राप्त राजस्व प्रकरण किसी भी स्थिति में लंबित न रहे समय से पूर्व पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्राप्त प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही डॉ भीमराव अंबेडकर योजना, संत रविदास योजना, भगवान बिरसा मुंडा योजना एवं टंट्या मामा योजना के अंतर्गत युवाओं के स्वरोजगार के हेतु जो प्रकरण बैंक में लगाए गए उन सभी प्रकरणों का फालोअप लेते हुए प्राथमिकता से सभी प्रकरण बैंक से स्वीकृत कराने एवं स्वीकृत राशि का वितरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि 31 मार्च से पूर्व शासन द्वारा दिए गए सभी लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाए।

कमिश्नर ने उद्यानकी विभाग की पीएफएमई, एवं अन्य विभाग की डॉ भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने उक्त योजनाओं में स्वरोजगार हेतु प्राथमिकता से बैंक से राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने आगामी ग्रीष्म काल को दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में तथा वन क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए की वह अभी से बंद पड़े एवं खराब हो चुके हैं पंप को सुधार कर जल संचयन की स्थिति में लाएं। ग्रीष्म काल के दौरान पेयजल संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर हैंडपंपों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य प्राथमिकता से करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग नरवाई की रोकथाम हेतु एवं किसानों को नरवाई ना जलाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पुनः खेत पाठशाला एवं कृषक संगोष्ठियों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर करें और लोगों को नरवाई ना जलाने के फायदे के बारे में समझाइश दे। उन्होंने निर्देश दिए की सभी कलेक्टर्स आगामी एक-दो दिनों में जल उपयोगिता समिति की बैठक भी आयोजित कर लें।

कमिश्नर ने कहा कि उन्नतशील किसानों को खेती की उन्नत तकनीकियों को के बारे में जानकारी देकर प्रोत्साहित किया जाए। सभी जिले से 100 -100 किसान चिंन्हित किया जाए जो जैविक खेती करने के लिए उत्सुक है। ऐसे किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ देते हुए जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि सप्ताह में एक दिन जिलों में जैविक हाट अनिवार्य रूप से लगाया जाए। इस जैविक हाट में जैविक उत्पादन, वस्तुएं एवं अभिकरण रखे जाएं जिसका ज्यादा से ज्यादा किसान एवं आम जनता लाभ उठा सके। उन्होंने खाद वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने उघानिकी फसलों के लिए क्लस्टर आधारित उद्यान तैयार करने, आवारा एवं निराश्रित गोवंश को रखने के लिए गौशालाओं की संख्या बढ़ाने एवं कामधेनु योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, बैतूल कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ऑनलाइन एवं संयुक्त आयुक्त विकास श्री नवल मीना, उपायुक्त विकास श्री डी एन पटेल, संभागीय सलाहकार आरसीएमएस श्री भूपेंद्र गुर्जर, उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग सुनील मित्रा सहित संभागीय अधिकारी गण ऑफलाइन उपस्थित रहे।

वन अधिकार दावों में देरी पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को लगाई फटकार

लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों में देरी पर लगेगा जुर्माना : कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने टीएल बैठक के दौरान वन ग्रामों के संपरिवर्तन, वन खण्डों के व्यवस्थापन तथा वन पट्टों की संख्या और रकबे के मिलान के कार्यों में लगातार हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने वन मित्र पोर्टल पर लंबित व्यक्तिगत वनाधिकार दावों के निराकरण में विलम्ब पर संबंधित वन एवं राजस्व अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन, वन खण्डों के व्यवस्थापन तथा वन पट्टों की संख्या और रकबे के मिलान का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन मित्र पोर्टल पर दर्ज व्यक्तिगत वनाधिकार दावों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि वनाधिकार से जुड़े प्रकरणों और वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन शासन की प्राथमिकता का कार्य है। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यों में इसी प्रकार की लापरवाही और देरी जारी रही तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिये जिले मे एचपीवी अभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने इस अभियान को अधिक गति प्रदान करने के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित बालिकाओं का समय सीमा में टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर एवं टीकाकरण की कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। इसके साथ ही विशेष टीकाकरण सत्रों का भी आयोजन किया जाये। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और भविष्य में महिलाओं को होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाऐगी। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी का उद्देश्य नागरिकों को तय समय-सीमा में शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी अधिकारी इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री रविंद्र परमार, श्री जमील खान, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, श्रीमती स्वाति मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रेम सिंह गौड़ सहित सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।

श्रमयोगी मानधन योजना में अधिक से अधिक पंजीयन के निर्देश

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की जनपद एवं नगरीय निकायवार समीक्षा के दौरान सभी जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिये कि योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना से जोड़ा जाए। पात्र श्रमिकों को योजना की जानकारी देकर उन्हें पंजीयन के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उन्हें भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सके। उन्होंने सीहोर नगर पालिका द्वारा सबसे कम पंजीयन किये जाने पर घोर नाराजगी जताई। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए तथा उन्हें इसके नुकसान के बारे में बताया जाए।

ाग के जिलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन

विदिशा (निप्र)। भोपाल संभाग के जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा उपार्जन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपार्जन केंद्रों की तैयारियां, पंजीकृत किसानों की स्थिति, भंडारण व्यवस्था, परिवहन, तौल व्यवस्था तथा किसानों को मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाए तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारियों को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव (एसीएस) ने निर्देश दिए कि गेहूं उपार्जन का कार्य गोदाम स्तरीय केन्द्रों पर ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। बैठक में एसीएस ने उपार्जन कार्य से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि गेहूं के परिवहन, उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तथा बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उपार्जन केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उपार्जन केंद्रों पर तौल कांटे, पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति की भी जानकारी ली गई। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि उपार्जित गेहूं के परिवहन और भंडारण की प्रक्रिया समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से की जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपार्जन केंद्रों की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्यों हेतु जारी एसओपी का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विदिशा जिले में एनआईसी वीसी कक्ष से कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बैठक में भाग लिया। इस दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अनिल तंतुवाय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने जिले में बनाए जाने वाले उपार्जन केंद्रों, बारदाना की उपलब्धता, तौल कांटों की व्यवस्था, परिवहन और भंडारण की तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य प्रारंभ होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं, ताकि किसानों से गेहूं खरीदी प्रक्रिया समय पर और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

कन्या महाविद्यालय में 'वर्मीकंपोस्ट एवं जैविक खेती' पर कार्यशाला आयोजित

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं के लिए 'वर्मीकंपोस्ट एवं जैविक खेती' विषय पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. बी.डी. अहिरवार के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के ईको क्लब द्वारा किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें जैविक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) और वर्मीकंपोस्ट (केंचुआ खाद) निर्माण की तकनीकी जानकारी प्रदान करना था। यह कार्यक्रम एप्को भोपाल के प्रायोजन से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ छात्राओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना भी रहा। इस अवसर पर 60 छात्राओं का पंजीयन कर उन्हें प्रशिक्षण किट भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षक एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री नीरज रघुवंशी, सीईओ नर्मदवाहिनी ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तथा श्री विवेक राय, सीईओ मध्य क्षेत्र समृद्ध कंसोर्टियम भोपाल उपस्थित रहे। श्री नीरज रघुवंशी ने छात्राओं को मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और रसायनों के बिना उच्च गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और उनसे अधिक मुनाफा प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। वहीं श्री विवेक राय ने छात्राओं को केंचुआ खाद बनाने की विधि, आवश्यक कच्चा माल जैसे कृषि अपशिष्ट और गोबर तथा इसके रखरखाव की जानकारी प्रायोगिक रूप से दी। कार्यक्रम का संचालन ईको क्लब संयोजक श्री राम आशीष यादव ने किया। इस अवसर पर सह-संयोजक श्रीमती नीतू दांगी, सचिव डॉ. शांता अहिरवार सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यशाला के पश्चात छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में स्थित वर्मीकंपोस्ट पिट का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने स्वयं भूसा और गोबर से वर्मीबेड तैयार कर केंचुआ खाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। छात्राओं ने खाद निर्माण की पूरी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से समझा और भविष्य में जैविक कृषि को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. बी.डी. अहिरवार ने छात्राओं को कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आत्मनिर्भरता का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।

कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर बनखेड़ी में कृषि विज्ञान मेला सम्पन्न

किसानों को दी गई उन्नत कृषि तकनीक, जैविक व प्राकृतिक खेती की जानकारी आत्मा योजनान्तर्गत जिला स्तरीय किसान विज्ञान मेला का कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर, बनखेड़ी सफलतापूर्वक आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 'आत्मा' योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर, बनखेड़ी में पिपरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए किसान भाई-बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बनखेड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष श्री हरीश मालानी, श्री नवल रघुवंशी, श्री सर्वज्ञ दीवान, भाऊसाहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास गोविंदनगर के उपाध्यक्ष श्री उम्मेद सिंह पटेल, श्री मकरन सिंह पटेल, सहसचिव श्री केशव माहेश्वरी, सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह पटेल, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री विवेक महेश्वरी, श्री अनिल बारोलिया, कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल, न्यास के प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र गुर्जर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य (मृदा विज्ञान) श्री नीतिराज पटेल, उपसंचालक कृषि डॉ.रविकांत सिंह, उप परियोजना संचालक 'आत्मा' श्री गोविंद मीना, कृषि वैज्ञानिक डॉ. दीपक खांडे, प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. संजीव कुमार गर्ग तथा कृषि एवं विभिन्न विभाग से पधारे अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्तिथ रहे साथ नर्मदापुरम के विभिन्न विकासखंडो से आए हुए किसान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए कार्यक्रम की शुरुआत में उपसंचालक कृषि डॉ. रविकांत सिंह ने कार्यक्रम का परिचय एवं रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस कृषि विज्ञान मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच उन्नत कृषि तकनीकों का प्रसार, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा किसानों को नवीन कृषि नवाचारों से अवगत कराना है।

नर्मदापुरम जिले के किसानों तथा विभागीय अमले को गेहूं कटाई उपरांत नरवाई जलाने की समस्या पर विशेष ध्यान देकर कृषकों को नरवाई प्रबंधन के लिए जागरूक करने के लिए कहाँ गया। उन्होंने कहाँ कि मिट्टी एक सजीव है, इसमें कई जीव- जंतु निवासरत है, जिसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए नरवाई जलाने से सजीव मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते ढ्ढ उन्होंने फसल विविधीकरन पर हमें ध्यान देने के लिए कहाँ गया ढ्ढ उन्होंने बताया की कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर जैविक एवं प्राकृतिक खेती का हब है जहाँ आकर सुकून मिलता है, उन्होंने किसानो से संतुलित मात्रा में उर्वरको का उपयोग करने की सलाह दी ढ्ढ उन्होंने किसानो से आग्रह किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान भाई अपनी भूमि को एग्रीस्टैक आई.डी से जुडवाए जिससे ई टोकन से संतुलित उर्वरक एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। पिपरिया विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी ने किसानो से नरवाई नहीं जलाने की अपील की गई, नरवाई जलाए नहीं बल्कि उसका चारा एकत्रित करें साथ ही फसल चक्र अपनाए जिससे नरवाई नहीं जलाना पढ़े एवं जो किसान भाई अच्छी उन्नत खेती कर रहे है उन कृषक एवं वैज्ञानिकों से किसान भाईयों को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । सांसद प्रतिनिधि एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य (मृदा विज्ञान) श्री नीतिराज पटेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी खेती आत्मनिर्भर खेती थी जो जमीन से जुड़ी हुई थी, उन्होंने वर्तमान में केंसर के बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की एवं इसे रोकने हेतु परिवार के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने के लिए आग्रह किया गया। श्री उम्मेद सिंह पटेल ने किसानों से आग्रह किया कि वे छोटे रकबे से ही जैविक खेती शुरू करें और धीरे-धीरे इसे बड़े स्तर पर अपनाए तथा विभाग की योजनाओं की जानकारी आधिक से अधिक किसानो तक पहुचाने की सलाह दी गई। श्री नवल रघुवंशी ने किसानों को भूमि सुपोषण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान पूरे देश में चैत्र नवरात्र से प्रारंभ होकर एक माह तक संचालित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भूमि की उर्वरता को बनाए रखना तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। श्री सर्वज्ञ दीवान ने किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जिले में कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर जैसी संस्था उपलब्ध है, जो पूर्णतः जैविक खेती पर कार्य कर रही है। किसानों को इस संस्था से मार्गदर्शन लेकर जैविक खेती को अपनाना चाहिए। तकनीकी सत्र के दौरान प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. संजीव कुमार गर्ग ने कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका, नरवाई प्रबंधन तथा प्राकृतिक खेती की पद्धतियों की जानकारी दी।

जंग के चलते कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप, घरेलू सिलेंडर की 7 दिन तक वेटिंग

रीवा में सिलेंडर 2000 का, कालाबाजारी के आरोप

भोपाल-इंदौर समेत कई शहरों में लगी थी लंबी कतारें, छिंदवाड़ा में शादियों में डीजल भट्टियों पर बनेगा खाना

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में 3 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप है। घरेलू सिलेंडर की वेटिंग भी 5 से 7 दिन की हो गई है। ऑयल कंपनियों ने 15 प्रतिशत गैस ही उपलब्ध होने की बात कही है, जो इमरजेंसी सेवा और घरों के लिए ही उपयोग हो सकेगी। कुछ शहरों के उपभोक्ता सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप लगा रहे हैं।

रीवा में गैस एजेंसी के बाद सुबह से कतार में लगे उमेश शुक्ला ने बताया कि दोपहर बाद तक सिलेंडर नहीं मिल पाया। दलाल 900 का सिलेंडर 1700 से लेकर 2000 रुपए तक में सिलेंडर बेच रहे हैं। उपभोक्ता मजबूरी में महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं।

इधर, ऑयल कंपनियों की सप्लाई के बाद कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ अस्पताल, सेना-पुलिस की कैंटीन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट स्थित कैंटीन, बस स्टैंड स्थित भोजनालय को ही मिलेंगे। हालांकि, खाद्य विभाग को जरूरत के हिसाब से ऑयल कंपनियों को लिस्ट देना होगी।

दूसरी ओर होटल, मैरिज गार्डन, सराफा कारीगरों के साथ भोपाल और इंदौर मेट्रो को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल सकेंगे। दोनों ही शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है, जिसमें वेल्डिंग के लिए एलपीजी का उपयोग होता है। छिंदवाड़ा के एक कैटरर्स का कहना है कि शादियों में गैस भट्टी पर रोक के कारण डीजल भट्टी से खाना बनाया जा रहा है।

स्टॉक इतना कि 48 घंटे तैसे-जैसे निकलेंगे- भोपाल होटल एसोसिएशन के तेजकुल पाल सिंह पाली का कहना है कि राजधानी में ही डेढ़ हजार से ज्यादा होटल और रेस्टॉरेंट हैं। जहां हर रोज 2 से ढाई हजार सिलेंडर उपयोग होते हैं। जिन होटल या रेस्टॉरेंट में स्टॉक है, वहां 48 घंटे ही तैसे-जैसे निकल पाएंगे।

इसके बाद होटल और रेस्टॉरेंट बंद हो जाएंगे। सरकार से मांग की है कि होटल, रेस्टॉरेंट और रेहड़ी वालों को कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए, लेकिन सरकार ने सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए गैस देने की बात कही है।

मार्च में ही 20 हजार से ज्यादा शादियां

प्रदेश में मार्च में ही 20 हजार से ज्यादा शादियां होना हैं। इनमें कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है, लेकिन ये 3 दिन से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शादियों में भोजन पकाने में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। भोपाल में 3 हजार आभूषण कारीगर हैं। इन्हें महीने में 9000 हजार सिलेंडर की जरूरत होती है।

दावा- घरेलू सिलेंडर की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, हकीकत-लंबी वेटिंग

जिम्मेदार दावा कर रहे हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत में लंबी वेटिंग है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में लंबी वेटिंग है। भोपाल के 5 नंबर इलाके में इसके लिए भीड़ देखी गई।

टीटी नगर इलाके में तो सिलेंडर के लिए भाग-दौड़ भी हो चुकी है। इंदौर में कमर्शियल सिलेंडर के संकट के बीच खाद्य विभाग के अधिकारी ने लकड़ी, कंडा, कोयला जैसे पारंपरिक ईंधन जलाने पर जोर दिया है। वहीं भोपाल में भी डीजल भट्टी का उपयोग करने की बात कही जा रही है। भोपाल के फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन का कहना है कि सरकार के नए निर्देश आए हैं। इसी हिसाब से सप्लाई व्यवस्था है। अब 25 दिन में ही सिलेंडर के लिए बुकिंग कराई जा सकेगी। सर्वर की दिक्कत आने और लोगों के द्वारा 1-2 सिलेंडर स्टॉक जमा करने की वजह से एजेंसियों के बाहर भीड़ लग रही है।

दाल, मसाले और ड्राई फ्रूट्स हुए महंगे

ईरान-इजरायल के बीच युद्ध का असर भोपाल के बाजारों में भी दिख रहा है। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री एवं कैट के पूर्व प्रवक्ता विवेक साहू ने बताया कि दालों में तेजी बनी हुई है। हरी मूंग करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 100 रुपए, चना 150 रुपए, मूंग मोगर लगभग 125 रुपए और चना दाल करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल तक तेज बताई जा रही है। वहीं, तूअर दाल के भाव में भी करीब 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मसालों के बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। थोक व्यापारी अनिल कुकरेजा के मुताबिक, मिर्ची लगभग 50 रुपए प्रति किलो और धनिया करीब 40 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। वहीं थोक ड्राई फ्रूट व्यापारी किशोर राजदेव के अनुसार, पिस्ता करीब 250 रुपए प्रति किलो, अंजीर 100 रुपए प्रति किलो, केसर लगभग 20 हजार रुपए प्रति किलो और दाल चीनी करीब 5 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है।

'फिल्म में काम करने गई थी और यह क्या कर लिया'

मोनालिसा की शादी से गुस्से में दादी, घर पर पसरा सन्नाटा

खरगोन (नप्र)। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा के उसके बॉयफ्रेंड से केरल में शादी कर लेने के बाद खरगोन जिले का महेश्वर में उसके घर सन्नाटा छाया हुआ है। जहां पिता और चाचा अब किसी का मोबाइल फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, वहीं घर पर अन्य परिजन उसके बारे में बात करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने वीडियो नहीं बनाने की ताकीद की।

आक्रोशित हो रहे हैं परिवार

मोनालिसा की फरमान खान से केरल में हिंदू मंदिर में शादी और विवाह के रजिस्ट्रेशन के बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। कल देर रात महेश्वर स्थित उसके घर पहुंचे खबर नवीसों को परिवार के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। पत्रकारों ने वहां जाकर पाया कि दादी प्रमिला घर के बाहर खाट पर मायूस सी बैठी हुई है। घर के फाटक अंदर से बंद थे ।

गुस्से से लाल थीं दादी

दादी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आसपास के घरों की महिलाएं व बालिकाएं भी दुखी और नाराज दिखाई दी। वे अपने समाज के अलावा अन्य समाज के व्यक्ति से मोनालिसा के विवाह से हैरान परेशान प्रतीत हुईं। दादी ने बताया कि मोनालिसा के पिता केरल से वापस लौट रहे हैं और चाचा कहीं बाहर गए हुए हैं। मोनालिसा की मां चने काटने गई हुई थी।

वह बताती तो हम ढूंढ देते

उन्होंने कहा कि मोना फिल्म में काम करने गई थी और यह क्या कर लिया । यदि वह शादी ही करना चाहती थी तो हमें बताती,समाज से कोई ठीक-ठाक व्यक्ति ढूंढ कर कर देते।

मोनालिसा से संपर्क नहीं

दादी ने बताया कि बुधवार सवेरे मोनालिसा से बात हुई थी उसके बाद से संपर्क नहीं हुआ। मोनालिसा के पिता जय सिंह केरल के पुलिस थाने गए थे लेकिन वहां से भगा दिया गया। उन्होंने बताया कि मोनालिसा के पिता को केवल हिंदी आती थी, वह दूसरी भाषा में बात नहीं कर पा रहा था। थाने में मोनालिसा से बात की तो उसने वापस आने से इनकार कर दिया। आज पड़ोस के लोगों ने भी तभी जुबान से कहा कि कम से कम परिवार की इज्जत का ख्याल करना था। हालांकि मोनालिसा का कहना है कि परिवार के लोग बुआ के लड़के से शादी करवा रहे थे।गौरतलब है कि प्रयागराज में मोनालिसा को देखकर उसे अपनी फिल्म में काम देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा ने इसे बगावत नहीं , लव जिहाद बताया था।

प्रदेश में अब दूध बेचने वालों के लिए लाइसेंस जरूरी

मिलावट रोकने की दिशा में बड़ा कदम, दूध ले जाने वाले उपकरणों की होगी निगरानी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अब डेयरी सहकारी समितियों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और दूध विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ऐसे सभी दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू करेगी।

इसके साथ ही दूध संग्रह, परिवहन में उपयोग होने वाले उपकरणों और भंडारण व्यवस्था की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। राज्य में ऐसे दूध उत्पादकों और विक्रेताओं की पहचान की जाएगी जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं। इसके अलावा दूध से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।

मप्र में 213 लाख टन दूध का उत्पादन- मध्यप्रदेश देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां देश के कुल दूध उत्पादन का करीब 9 प्रतिशत यानी लगभग 213 लाख टन दूध का उत्पादन होता है। राज्य में सांची दूध प्रमुख डेयरी ब्रांड है और ग्रामीण क्षेत्रों में दूध संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 381 नई सहकारी समितियां भी कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में पिछले वर्ष नेशनल डेयरी डव्लपमेंट बोर्ड के साथ अनुबंध भी किया गया था।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल दूध उत्पादन का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा भैंस के दूध का है। वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 652 से 707 ग्राम प्रतिदिन रही।

25 गाय रखने पर 10 लाख का प्रोत्साहन- प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत 25 गायों की यूनिट स्थापित करने पर 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

केंद्र ने भी मांगी दूध उत्पादन की रिपोर्ट- दूध उत्पादन और बिक्री को लेकर केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए पंजीकरण या लाइसेंस अनिवार्य करने संबंधी नई एडवाइजरी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को छोड़कर सभी दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत पंजीकरण या लाइसेंस लेना होगा। एफएसएसएआई के अनुसार कुछ दूध उत्पादक और विक्रेता बिना पंजीकरण या लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय चला रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी रखें ध्यान

प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में दूध कारोबारियों की निगरानी बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी के पास आवश्यक पंजीकरण या लाइसेंस हो। साथ ही दूध संग्रह और परिवहन में उपयोग होने वाले उपकरणों तथा भंडारण व्यवस्था की समय-समय पर जांच भी की जाए। एफएसएसएआई ने राज्यों को विशेष पंजीकरण अभियान चलाकर ऐसे दूध उत्पादकों और विक्रेताओं की पहचान करने को भी कहा है जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं। इसके अलावा दूध से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और अनुपालन की रिपोर्ट हर महीने 15 और 30 या 31 तारीख तक प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

आयुष्मान में एनएबीएच फाइनल लेवल अनिवार्य होते ही सक्रिय एजेंट

अस्पतालों को दो-ढाई लाख के पैकेज का ऑफर, 336 अस्पताल योजना से बाहर होने की आशंका

भोपाल (नप्र)। आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों के लिए एनएबीएच फाइनल लेवल सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद नया विवाद सामने आया है। नर्सिंग होम एसोसिएशन का दावा है कि इस फैसले के बाद निजी कंपनियां और एजेंट सक्रिय हो गए हैं। ये एजेंट अस्पतालों में पहुंचकर एनएबीएच सर्टिफिकेट दिलाने के नाम पर दो से ढाई लाख रुपए तक के पैकेज ऑफर कर रहे हैं। इसमें आवेदन से लेकर कागजी प्रक्रिया और सर्टिफिकेट दिलाने तक की जिम्मेदारी लेने की बात कही जा रही है। एसोसिएशन ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सरकार के फैसले का विरोध किया है और कोर्ट जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

बैठक में सामने आया एजेंटों का मामला- नर्सिंग होम एसोसिएशन की बुधवार को हुई बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान योजना में एनएबीएच फाइनल लेवल की अनिवार्यता लागू होते ही कई निजी कंपनियां और एजेंट सक्रिय हो गए हैं। ये एजेंट सीधे अस्पताल संचालकों से संपर्क कर रहे हैं और एनएबीएच सर्टिफिकेट दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। इसके लिए वे दो से ढाई लाख रुपए तक का पैकेज बता रहे हैं। इस पैकेज में आवेदन करने, जरूरी दस्तावेज तैयार कराने और पूरी प्रक्रिया पूरी कर सर्टिफिकेट दिलाने की जिम्मेदारी लेने की बात कही जा रही है।

चार बड़े शहरों के अस्पतालों पर सबसे ज्यादा असर- सरकार का यह नियम फिलहाल मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के निजी अस्पतालों पर लागू किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक इन शहरों में कुल 395 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। इनमें से 212 अस्पताल पिछले करीब पांच साल से एनएबीएच के एंट्री लेवल सर्टिफिकेट पर ही काम कर रहे हैं। वहीं, केवल 59 अस्पतालों के पास ही फुल एनएबीएच सर्टिफिकेट है। ऐसे में करीब 336 अस्पतालों के योजना से बाहर होने की स्थिति बन सकती है।

अस्पतालों को मिला 15 दिन का अतिरिक्त समय

स्थिति को देखते हुए आयुष्मान कार्यालय ने सभी अस्पताल संचालकों को एक ई-मेल भेजा है। इसमें एनएबीएच सर्टिफिकेट के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब जिन अस्पतालों ने 31 मार्च तक एनएबीएच सर्टिफिकेट नहीं कराया है, उन्हें 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसके बाद 16 अप्रैल के बाद स्टेट हेल्थ अथॉरिटी इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा।

नर्सिंग होम एसोसिएशन जाएगा हाईकोर्ट- इस फैसले के विरोध में नर्सिंग होम एसोसिएशन ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। एसोसिएशन का कहना है कि इतने कम समय में सभी अस्पतालों के लिए एनएबीएच फाइनल लेवल हासिल करना संभव नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर जबलपुर में नर्सिंग होम एसोसिएशन की ओर से एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका पर 16 मार्च को सुनवाई होना तय है।

छोटे शहरों के अस्पतालों के सामने बड़ी चुनौती- नर्सिंग होम एसोसिएशन के सचिव डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि प्रदेश के कई शहरों में एनएबीएच सर्टिफाइड अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उज्जैन में केवल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अस्पताल ही एनएबीएच सर्टिफाइड है, जबकि बाकी अस्पतालों के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के इस फैसले का पूरे प्रदेश के निजी अस्पताल संचालक विरोध कर रहे हैं और अपनी बात सरकार व अन्य मंचों तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है।

गुना में कमरे से दंपत्ति के सड़े हुए शव मिले

पत्नी जमीन पर मृत, युवक फंदे पर लटका था; आशंका- हत्या के बाद पति ने सुसाइड किया

गुना (नप्र)। गुना के रूठियाई इलाके में गुरुवार दोपहर पति-पत्नी की लाश मिली है। लाश तीन से चार दिन पुरानी बताई जा रही है। पूरी तरह काली पड़ने के साथ ही बॉडी डीकंपोज होने लगी थी। प्रारंभिक जानकारी अनुसार, आशंका है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की होगी, फिर खुद सुसाइड किया होगा।

धरनावदा थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे ने बताया कि मृत युवक का नाम सूरज सहरिया (24) है। वह बजरंगगढ़ की बीस भुजा कॉलोनी का रहने वाला था। वहीं युवती का नाम आरती है। उसकी गुमशुदगी का मामला बजरंगगढ़ थाने में दर्ज है। दोनों रूठियाई में ईंट भट्टों के पास बने कमरे में रह रहे थे।

शनिवार को हुई थी बात- विनोद ने बताया कि उसकी अपने भाई सूरज से शनिवार को आखिरी बार बात हुई थी। उसने कहा था कि तू रूठियाई आ जा, अपन काम करेंगे। सूरज ईंट भट्टे पर मिट्टी बाहर फेंकने का काम करता था। वहीं उसकी पत्नी पानी लेकर बैठी रहती थी।

दोनों के चेहरों पर होली का कलर भी लगा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रंगपंचमी वाले दिन दोनों ने होली भी खेली थी। एक दूसरे को जमकर रंग लगाया था। उसी के बाद से ही किसी ने उन्हें नहीं देखा। जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल के द्वारा दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया है।

भाई पास वाले ईंट भट्टे पर रहता है

सूरज का भाई पास ही दूसरे ईंट भट्टे पर रहता है। पिछले दो दिन से दोनों दिखाई नहीं दिए। बुधवार रात भाई ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो वह वापस चला गया। आज (गुरुवार) सुबह भाई फिर कमरे पर गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसे देखकर उसे शक हुआ। उसने गेट तोड़कर अंदर देखा। कमरे के अंदर युवती की बॉडी जमीन पर पड़ी थी, जबकि युवक का शव फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पहले यह जानकारी सामने आई थी कि दोनों लिव इन में रह रहे थे। लेकिन, युवक के बड़े भाई विनोद ने बताया कि दोनों ने लगभग छह महीने पहले शादी कर ली थी। उसने मुझे आकर फोटो दिखाई थी कि टेंशन मत ले मैंने शादी कर ली है।

मंत्रालय के कर्मचारी फिर लामबंद, आंदोलन की तैयारी

कैशलेस हेल्थ स्कीम, चौथा समयमान वेतनमान मुख्य मांगें, राजभवन-विधानसभा के कर्मचारी भी हो सकते हैं शामिल

भोपाल (नप्र)। चौथा समयमान वेतनमान, स्थायीकर्मियों को सातवां वेतनमान नहीं दिए जाने और कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं होने के विरोध में मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यह आंदोलन 19 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जाएगा। मंत्रालय के साथ-साथ विधानसभा और राजभवन के कर्मचारियों से भी इसमें शामिल होने की अपील की जाएगी।

मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक ने बताया कि मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारियों की कई न्यायोचित मांगें लंबे समय से लंबित हैं। कई बार ज्ञापन देने और चर्चा के बावजूद अधिकारियों द्वारा समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। इसी के चलते संघ की कार्यकारिणी समिति की आपात बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय में 2020 के आदेश का पालन नहीं- नायक के अनुसार प्रदेश के अन्य विभागों में चौथा समयमान वेतनमान लागू किया जा चुका है, लेकिन मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी अब भी इससे वंचित हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 मार्च 2020 को सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि राज्य प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर समयमान वेतनमान के साथ उच्च पदनाम देकर पदोन्नति का समाधान निकाला जाए।

इन निर्देशों के अनुसार कोष एवं लेखा, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और जनजातीय कार्य विभाग में कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने ही पांच साल बाद भी अपने निर्देशों का पालन नहीं किया।

कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना अब तक लागू नहीं- संघ अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है, जबकि इससे शासन पर कोई अतिरिक्त व्यय भार भी नहीं आएगा। इसके अलावा स्थायीकर्मियों को अभी तक सातवां वेतनमान नहीं मिला है।

तीन साल बाद भी घोषित नहीं हुआ परिणाम- उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के काम के घंटे, अवकाश और पद के अनुरूप न्यूनतम वेतन का भी पालन नहीं किया जा रहा है। मंत्री स्थापना और मंत्रालय स्थापना में कार्यरत आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम तीन साल बाद भी घोषित नहीं हुआ है और न ही दूसरी परीक्षा कराई गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तर्ज पर 25 वर्ष में पूर्ण पेंशन योग्य सेवा का प्रावधान भी लागू नहीं किया गया है।

अन्य संगठनों से भी आंदोलन में शामिल होने की चर्चा

इन सभी मुद्दों सहित 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। नायक ने बताया कि मंत्रालय के शीघ्रलेखक संघ और अजाक्स संगठन से भी आंदोलन में शामिल होने के लिए बातचीत की जा रही है। विधानसभा, विधि विभाग और राजभवन के कर्मचारियों को भी चौथा समयमान वेतनमान नहीं मिला है, इसलिए उनसे भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है।

जल्द घोषित की जाएंगी आंदोलन की तिथियां

उन्होंने कहा कि आंदोलन के चरण और तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। आंदोलन की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्य सुरक्षा अधिकारी को दे दी गई है।